● वर्ष-6
● अंक-86
रायपुर, गुरुवार
05 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8>> मुख्यमंत्री साय ने जशपुर...

अग्निवीरों को सेवा विस्तार स्थायी भर्ती का खुला रास्ता



नयी दिल्ली। 'अग्निपथ' योजना में बड़े बदलाव के तहत सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर सेना से सेवामुक्त होने वाले 'अग्निवीरों' को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया जाएगा। इसके बाद निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने और व्यक्तिगत सहमति देने वाले अग्निवीरों को स्थायी भर्ती की पेशकश की जाएगी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने यह घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैन्य भर्ती योजना में तीनों सेनाओं की सिफारिशों के अनुरूप बदलावों को मंजूरी दिए जाने के तुरंत बाद की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कदम सशस्त्र बलों में किए जा रहे 'दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों' का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 'युवा, तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार सेना' का निर्माण करना है। जून 2022 में शुरू की गई 'अग्निपथ' योजना के तहत सैनिकों की भर्ती चार साल के कार्यकाल के लिए की गई। इसमें कुल भर्ती किए गए अग्निवीरों में से केवल 25 प्रतिशत को नियमित सेवा में बनाए रखने का प्रावधान था।

योजना में ये बदलाव करीब 18,000 अग्निवीरों के सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होने के तीन सप्ताह से कुछ अधिक समय पहले किए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीडीएस ने कहा, ''आज भारतीय सशस्त्र बलों और अग्निवीरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मंत्रिमंडल ने सभी अग्निवीरों के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने का रास्ता खोल दिया है।'' फिलहाल अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए तीन लाख से अधिक सैनिक सशस्त्र बलों में सेवा दे रहे हैं।

जनरल सुब्रमणि ने कहा, ''मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर नियमित बलों में शामिल किया जाता है, जबकि शेष 75 प्रतिशत अनुशासित और प्रेरित युवाओं के रूप में सेवामुक्त हो जाते हैं।'' उन्होंने कहा, ''नए बदलावों के तहत इन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा अवधि की पेशकश की जाएगी। इस विस्तारित अवधि के पूरा होने के बाद चयन मानदंडों को पूरा करने वाले और सेवा जारी रखने के इच्छुक अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।'

सैटेलाइट-आधारित नेविगेशन सिस्टम को मिली ताकत

नई दिल्ली। भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम, नाविक को एक बड़ा बढ़ावा मिला है। इसरो ने अपने नवीनतम उपग्रह, एनवीएस-03 को उसकी निर्धारित जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थापित करने के लिए, उससे जुड़ी तीसरी और अंतिम ऑर्बिट-रेज़िंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 30 अक्टूबर 2026 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, अपने जीएसएलवी-एफ 18 रॉकेट के ज़रिए इस उपग्रह को लॉन्च किया था। सफल लॉन्च के बाद, एनवीएस-03 को पहले एक शुरुआती ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा गया, और फिर इसे और ऊँचाई पर पहुँचाने के लिए कई बार इसकी कक्षा में बदलाव (मैनुवर) किए गए। इसरो ने अब कक्षा को ऊँचा करने की तीसरी और अंतिम प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिससे उपग्रह 35,842.6 × 34,594.9 द्यद्व की जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थापित हो गया है। यह सफल तैनाती भारत के स्वतंत्र नेविगेशन नेटवर्क की पूरी पोजिशनिंग क्षमताओं को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन भारत का अपना सैटेलाइट-आधारित नेविगेशन सिस्टम है, जो अमेरिका



केग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के समान है। यह पूरे भारतीय भू-भाग और देश की सीमाओं से लगभग 1,500 द्यद्व आगे तक के क्षेत्र में सटीक लोकेशन और समय की जानकारी प्रदान करता है। इसके सिग्नलों का इस्तेमाल स्मार्टफोन, वाहनों, जहाजों, ट्रेनों और अन्य उपकरणों द्वारा नेविगेशन और ट्रैकिंग के लिए किया जा सकता है। हालांकि, कुछ पूर्व उपग्रहों पर लगे परमाणु घड़ियों में खराबी के कारण उपग्रह समूह कमजोर हो गया था।

एक पूर्व प्रतिस्थापन उपग्रह, एनवीएस-02, भी प्रणोदन प्रणाली की समस्या के कारण अपने निर्धारित कक्षा तक नहीं पहुंच सका। इससे ह्ड्ड1द्बष्ट के पास स्वतंत्र रूप से पूर्ण स्थिति निर्धारण सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक चार परिचालन उपग्रहों से कम उपग्रह रह गए थे। एनवीएस-03 से इस न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने की उम्मीद है। इस उपग्रह में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु घड़ी लगी है, जो अतिरिक्त घड़ी प्रणालियों के साथ सटीक समय बनाए रखने में मदद करती है। यह रू आवृत्ति बैंड का भी समर्थन करता है, जिससे एनएवीआईसी सिग्नल आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले स्मार्टफोन चिप्स और नेविगेशन रिसीवरों के लिए अधिक सुलभ हो जाते हैं।

एक चालू एनएवीआईसी प्रणाली भारत को विदेशी सैटेलाइट नेटवर्क पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, महत्वपूर्ण नेविगेशन और टाइमिंग सेवाओं पर बेहतर नियंत्रण देती है। इस तरह की क्षमताएं रोज़मर्रा के नेविगेशन के साथ-साथ आपातकालीन स्थिति, परिवहन, समुद्री कार्यों, बुनियादी ढांचे और रणनीतिक उपयोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एनवीएस-03 को लगभग 12 वर्षों तक काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालाँकि, अपने निर्धारित ऑर्बिट (कक्षा) में पहुँचने का मतलब यह नहीं है कि सभी सेवाएँ तुरंत उपलब्ध हो जाएँगी।

खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षों में 2,814 करोड़ रुपये की कैपेक्स सहायता योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य लिथियम, निकेल और कोबाल्ट की घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाना तथा आयात पर निर्भरता कम करना है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और रक्षा जैसे भविष्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। ऊर्जा परिवर्तन और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए पांच वर्षों में कुल 2,814 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भविष्य को ऊर्जा देने वाली परिष्कृत सामग्रियों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहने के जोखिम को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि हमारे भविष्य को ऊर्जा देने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना चाहिए?





एशियन हॉकी चैंपियंस: फाइनल में टीम इंडिया

चंडीगढ़। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से करारी शिक्स्त दी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे मैच में दमदार प्रदर्शन किया और कोरियाई टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय टीम आक्रामक नजर आई। शिलानंद लाकरा ने चौथे मिनट में गोल करके भारत का खाता खोला। हालांकि, दक्षिण कोरिया ने नौवें मिनट में सांगजुन हन के गोल से बराबरी हासिल कर ली। इसके तुरंत बाद भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल में बदलकर टीम को 2-1 से आगे कर दिया। 13वें मिनट में शिलानंद ने अपना दूसरा गोल दागते हुए भारत की बढ़त 3-1 कर दी। दूसरे क्वार्टर में भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा जारी रहा। सुखजीत सिंह ने 21वें मिनट में गोल करके स्कोर 4-1 किया। इसके बाद दिलप्रीत सिंह ने शानदार खेल दिखाते हुए 21वें और 25वें मिनट में लगातार दो गोल दागे। इस तरह मध्यांतर तक भारत ने 6-1 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली।

दिल्ली से चलता है पंजाब, सुबह से शराब की बू आती थी: राहुल गांधी

चंड़ीगढ़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य को दिल्ली से चलाया जा रहा है और सरकार नशीले पदार्थों की समस्या (ड्रग्स की समस्या) को रोकने में नाकाम रही है। संगरूर में कांग्रेस की इंसाफ रैली को संबोधित करते हुए, गांधी नेचिट्टा (मिलावटी हेरोइन) को पंजाब की एक बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा कि कई साल पहले मैंने कहा था कि पंजाब में नशीले पदार्थों का प्रसार हो रहा है। उस समय बीजेपी और अकाली दल ने यह कहकर बात को टाल दिया था कि राहुल गांधी को पंजाब के बारे में कुछ नहीं पता है। गांधी ने कहा लोगों को एक ऐसी सरकार चाहिए जो पंजाब के लिए काम करे। न कि आप जैसी सरकार, जो दिल्ली से चलाई जाती है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह और वरिष्ठ नेता प्रताप बाजवा, विजय इंदर सिंगला, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजिंदर कौर भट्टल और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी मौजूद थे। गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस



आरोप पर खुली बहस की चुनौती दी कि कांग्रेस राष्ट्र-विरोधी है। उन्होंने मोदी से कहा कि वे किसी भी मंच पर आकर उनका सामना करें। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा कराने की मोदी की बार-बार की मांग बेमानी है, क्योंकि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और जब वे (गांधी) बोलने की कोशिश करते हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। गांधी ने कहा कि दिल्ली से पंजाब की सरकार नहीं चलती है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अपनी राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों के भीतर से ही चलाती है। उन्होंने कहा न तो केंद्रीय गृह मंत्री पंजाब चलाते हैं और न ही दिल्ली से कोई मुख्यमंत्री पंजाब चलाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब सरकार पर नियंत्रण रखे हुए हैं, जबकि मान को उनके प्रभाव में रहकर ही सरकार चलानी पड़ रही है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

मोदी व योगी जैसे माटी के लाल करेंगे देश का नेतृत्व : नितिन

गोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का नेतृत्व तथाकथित युवराज नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे 'माटी के लाल' करेंगे। गोरखपुर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान को संबोधित करते हुए नवीन ने विपक्ष पर चुनावी हार के बाद बहाने बनाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी को 'पार्ट टाइम नेता' करार देते हुए कहा कि वह केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं जबकि भाजपा के कार्यकर्ता पूरे वर्ष जनता की सेवा करते हैं। नवीन ने कहा, राहुल गांधी जी, भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत है कि आपके जैसे कितने भी तथाकथित युवराज आ जाएं, वे आएंगे और चले जाएंगे। इस देश का नेतृत्व इसी माटी के लाल नरेन्द्र मोदी और योगी आदित्यनाथ करेंगे।



ईडी : तीन फर्जी कॉल सेंटर, 220 लोग और निशाने पर

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मंगलवार को चार आरोपियों हर्षिल नयनभाई रावल, जसवंत सिंह, चेतन मुंजाल और प्रणव पिठाडिया को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई है। इन आरोपियों को हैदराबाद के नामपल्ली स्थित विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया, जहां अदालत ने चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों ने तीन जगहों पर फर्जी कॉल सेंटर खोल रखा था। उसमें 220 लोग काम कर रहे थे। कॉल सेंटर से अमेरिकन लोगों को यह कह कर फोन किया जाता था कि वे यूएस की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बोल रहे हैं। अमेरिकन लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे वसूली की जाती थी। ईडी ने इसी मामले में पहले विकास निमार (27.07.2026 को), ताराचंद निमार (05.08.2026 को) और मो. इरफान अंसारी (10.08.2026 को) को गिरफ्तार किया था।

अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में पार्टी ऑफिस पर छापा

कोलकात। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर के सरिषा इलाके में पार्टी के एक कार्यालय से पुलिस ने एक करोड़ दो लाख 79 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, यह रकम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित राय से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर बरामद की गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम पार्टी कार्यालय में क्यों रखी गई थी और इसका स्रोत क्या है। उल्लेखनीय है कि अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से टीएमसी के सांसद हैं। डायमंड हार्बर पुलिस ने मंगलवार रात सरिषा स्थित तृणमूल के एक कार्यालय में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के अतिरिक्त अधीक्षक अभिषेक मजूमदार के अनुसार, सुमित राय से हिरासत में पूछताछ के दौरान कुछ अहम सुराग मिले थे। इन्हीं के आधार पर पुलिस ने कार्यालय में छापा मारा और वहां से 1,02,79,000 रुपये नकद बरामद किए।

मुश्किल में सीजेपी की रत्ना मजिस्ट्रेट पर टिप्पणी पड़ी भारी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अमोल सिन्हा ने कॉकरोच जनता पार्टी की विधि प्रमुख रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी है। यह अनुमति दिल्ली की एक अदालत के न्यायिक अधिकारी के खिलाफ उनके सोशल मीडिया संदेशों को लेकर दी गई है। वकील कौशिक चटर्जी के आवेदन पर यह कदम उठाया गया। सिन्हा ने दो नवंबर को लिखे एक पत्र में न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 15(2) के तहत कार्रवाई की सहमति दी। मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रत्ना सिंह के संदेशों से जुड़ा है। इन संदेशों में उन्होंने साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे के आदेश पर असंतोष जताया था। यह आदेश दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें कथित हिरासत में लिए जाने से संबंधित था। सिन्हा ने कहा कि संदेश केवल न्यायिक आदेश की आलोचना तक सीमित नहीं थे। प्रथम दृष्टया यह संकेत मिला कि मजिस्ट्रेट किसी बाहरी सत्ता के निर्देशों पर काम कर रहे थे।

भारतीय रेलवे खाद्यान्न और कोयले की ढुलाई में ज्यादा तेजी

, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने अक्तूबर 2026 में माल ढुलाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान रेलवे ने 145.07 मिलियन टन माल की ढुलाई की। यह अक्तूबर 2025 के 133.93 मिलियन टन के मुकाबले 8.32 प्रतिशत अधिक है। खाद्यान्न, घरेलू कोयले और अन्य प्रमुख वस्तुओं की ढुलाई में वृद्धि से रेलवे के प्रदर्शन को मजबूती मिली है। अक्तूबर में खाद्यान्नों की ढुलाई 26.3 प्रतिशत बढ़ी। घरेलू कोयले की ढुलाई में 16 प्रतिशत और अन्य माल में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा क्लिंकर में 10.4 प्रतिशत, घरेलू कंटेनरों में 6.3 प्रतिशत, लौह अयस्क में 5 प्रतिशत, खनिज तेल में 1.9 प्रतिशत और तैयार स्टील की ढुलाई में 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। बिजली घरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले की आपूर्ति भी बढ़ाई गई। अक्तूबर 2026 में रेलवे ने प्रतिदिन औसतन 469.8 रेक कोयले की आपूर्ति की। अक्तूबर 2025 में यह आंकड़ा 393.2 रेक प्रतिदिन था। इस तरह बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से अक्तूबर के बीच रेलवे ने कुल 978.78 मिलियन टन माल की ढुलाई की।



ट्रंप को लगा झटका, अमेरिकी मध्यावधि चुनाव रचा गया इतिहास

वाशिंगटन। अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और इस बार का परिणाम वाकई चौंकाने वाला रहा है। देश भर के मतदाताओं ने अपनी वोटिंग से इतिहास रच दिया है, क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में ऐसे नेताओं की जीत हुई है जो अब तक राजनीति के मुख्य केंद्र से दूर थे। खास बात यह है कि इस चुनाव के बाद अमेरिकी संसद के दोनों सदनों यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। इस बड़े सियासी उलटफेर से रिपब्लिकन पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, जो पहले दोनों सदनों पर काबिज थी। संसद में डेमोक्रेट्स के मजबूत होने से अब न सिर्फ उनके पास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को रोकने की ताकत आ गई है, बल्कि वे खुलकर उनकी नीतियों और फैसलों की जांच भी कर सकेंगे।

इस चुनाव में कई राज्यों के गवर्नर्स पदों पर ऐतिहासिक और चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिले हैं। आइए जानते हैं कि किस राज्य में किसने बाजी मारी और क्या नए रिकॉर्ड बने। जॉर्जिया और फ्लोरिडा का सियासी उलटफेर- जॉर्जिया में डेमोक्रेट की कीशा लांस बॉटम्स ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है और वह राज्य की पहली महिला और पहली अश्वेत गवर्नर बन गई हैं। वहीं, फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी के बायरन डोनाल्ड्स ने जीत हासिल कर राज्य के पहले अश्वेत गवर्नर होने का गौरव हासिल किया है।

टेक्सास और ओहियो में महिलाओं का दबदबा- टेक्सास में डेमोक्रेट गीना हिनोजोसा ने रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट को हराकर पिछले तीन दशकों से चली आ रही पार्टी की बादशाहत को खत्म कर दिया है और वह राज्य



की पहली लातिना गवर्नर बन गई हैं। इसके अलावा ओहियो में एमी एकटन ने जीत हासिल कर वहां की पहली महिला गवर्नर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

कैलिफोर्निया और विस्कॉन्सिन के नए चेहरे- कैलिफोर्निया में पूर्व कैबिनेट सचिव जेवियर बेसेरा को राज्य का पहला निर्वाचित लातिनो गवर्नर चुना गया है, जबकि विस्कॉन्सिन में डेविड क्रॉउली ने जीत हासिल कर राज्य के पहले ब्लैक गवर्नर होने का मील का पत्थर छुआ है।

संसद के ऊपरी और निचले सदनों में इस बार जो चेहरे जीतकर पहुंचे हैं, उन्होंने देश की राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। अब्दुल अल-सईद की ऐतिहासिक जीत- मिचेल से अब्दुल अल-सईद ने सीनेट सीट जीतकर अमेरिकी संसद के इतिहास में पहले मुस्लिम सीनेटर बनने का बड़ा मुकाम हासिल किया है। वहीं न्यू हैम्पशायर में क्रिस पापस ने जीत दर्ज कर देश के पहले खुले तौर पर समलैंगिक पुरुष अमेरिकी सीनेटर होने का रिकॉर्ड बनाया है।

साउथ कैरोलिना और टेक्सास का चुनावी परिणाम- साउथ कैरोलिना में एनी एंड्रयूज ने शानदार जीत हासिल करते हुए राज्य की पहली निर्वाचित महिला अमेरिकी सीनेटर बनने का गौरव प्राप्त किया, जबकि टेक्सस में जेम्स टैलारिको ने जीत दर्ज कर तीन दशकों में राज्य से सीनेट पहुंचने वाले पहले डेमोक्रेट बने हैं। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के नए सांसद- न्यू जर्सी में एडम हमवी वहां के पहले मुस्लिम कांग्रेस सदस्य चुने गए हैं, जबकि न्यूयॉर्क में क्लेयर वाल्देज़ राज्य से पहली महिला मूल अमेरिकी (नेटिव अमेरिकन) कांग्रेस सदस्य बनकर संसद पहुंची हैं।

संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हुए इस नाटकीय बदलाव के बाद अब शीर्ष नेतृत्व में भी ऐतिहासिक फेरबदल होने जा रहा है। डेमोक्रेट्स की इस बड़ी जीत के बाद मौजूदा अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफ्रीस के देश के पहले अफ्रीकी अमेरिकी स्पीकर ऑफ द हाउस बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

कांग्रेस ने साय सरकार पर साधा निशाना, एनएच 30 किया जाम

■ बस्तर में बाढ़ ने किसानों की दुर्गति कर दी है. अन्नदाताओं को मुआवजा देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने चक्काजाम किया है.



जगदलपुर। बस्तर में आई बाढ़ ने नदी किनारे बसने वाले लोगों और किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाढ़ की वजह से कई लोगों के आशियाने ढह गए, लाखों हेक्टेयर फसल पूरी तरह बर्बाद हो गए। बाढ़ के बाद जिला प्रशासन और सरकार बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा राशि प्रदान कर रही है। लेकिन यह मुआवजा राशि किसानों के लिए बेहद कम साबित हो रहा है। बीते दिनों किसान और कांग्रेस पार्टी ने बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता पहुंचाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। मुआवजा राशि के लिए बस्तर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था। मांग पूरी नहीं होने पर बुधवार 4 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया। नेशनल हाईवे 30 आमागुड़ा चौक पर करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। जाम की वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। 1 घंटे के बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस बल ने मार्ग से हटाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य का कहना है कि चक्काजाम करने का प्रमुख कारण छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का किसानों के प्रति ढुलमुल रवैया है। सितम्बर महीने में आई बाढ़ ने सबकुछ तबाह किया। जिसको लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। हमने मांग की थी कि किसानों का केसीसी लोन माफ किया जाए, प्रति एकड़ 65 हजार रुपये मुआवजा राशि दिया जाए। आंशिक क्षति को देखते हुए 1 लाख रुपये दिए जाएं। कच्चे मकान की पूर्ण क्षति के लिए 3 लाख रुपये दिए जाएं। अब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार किसानों की आवाज को अनसुना कर रही है। यही वजह है कि आज कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर चक्काजाम कर रहे हैं। हम राज्य सरकार को आगाह कर रहे हैं कि किसानों की आवाज सुनिए। बस्तर में बड़े बड़े आयोजनों में करोड़ो रूपये खर्च हो रहे हैं। परंतु किसानों के कर्जा माफ के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है- सुशील मौर्य, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस सुशील मौर्य ने आगे कहा कि बस्तर में हस्ष्ट स्टील प्लांट चला रहा है। उसके बावजूद बस्तरवासियों और किसानों के लिए पैसे नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किसानों के हित में कांग्रेस आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी।

1 करोड़ से ज्यादा का धान और बारदाना का गबन, दो गिरफ्तार



भानुप्रतापपुर। कांकेर जिले से धान खरीदी के नाम पर सरकारी व्यवस्था में बड़ी अनियमितता का मामला सामने आया है। भानुप्रतापपुर विकासखंड के आसुलखार धान खरीदी केंद्र की जांच में 4,651 क्विंटल से अधिक धान और 11 हजार से ज्यादा बारदाने की कमी पाई गई है। इस अनियमितता से शासन को करीब 1 करोड़ 44 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। दरअसल, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित आसुलखार के धान खरीदी केंद्र में कुल 748 किसानों से 36 हजार 703 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। इसके विरुद्ध 30 हजार 855 क्विंटल धान का ही उठाव होना दर्ज किया गया। जब मामले की जांच और भौतिक सत्यापन किया गया, तो 11 हजार 628 बोरा बारदाना और 4651 क्विंटल धान की कमी सामने आई। इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 44 लाख 18 हजार 720 रुपये आंकी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर खाद्य शाखा द्वारा 10 जून 2026 को जांच समिति गठित की गई थी। खाद्य निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक की संयुक्त टीम ने जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जांच में धान खरीदी प्रभारी टिकेश्वर पोटाई और बारदाना प्रभारी भोज कुमार जैन की भूमिका सामने आने के बाद समिति प्रबंधक परमेश महावीर की रिपोर्ट पर भानुप्रतापपुर थाने में अपराध क्रमांक 226/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में धान खरीदी प्रभारी टिकेश्वर पोटाई और बारदाना प्रभारी भोज कुमार जैन को गिरफ्तार किया। दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया।

ननि की महत्वपूर्ण फाइलें गायब !निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल

दुर्ग। दुर्ग नगर निगम की स्थापना शाखा से महत्वपूर्ण फाइलें चोरी होने की आशंका पैदा हो गई है। दरअसल, निगम कार्यालय के स्थापना शाखा में रखी गई आलमालियों के ताले टूटे पाए गए हैं, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवालों को जन्म दिया है। दरअसल, दुर्ग नगर निगम की स्थापना शाखा में सोमवार को स्थापना शाखा के कमरे और आलमारी का ताला टूटा हुआ पाया गया। इस विभाग से महत्वपूर्ण फाइलें चोरी होने की जानकारी सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में है। सवाल यह है कि आखिर निगम कार्यालय के भीतर से फाइलें कैसे गायब हो गईं? क्या कार्यालय में आने-जाने वालों पर नजर रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है? और सबसे अहम बात, क्या निगम परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में इस पूरे मामले से जुड़ी कोई गतिविधि रिकॉर्ड हुई है? महापौर अलका बाघमार ने मीडिया से चर्चा में बताया कि जानकारी मिली है कि निगम की आलमारी तोड़ी गई है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा कि क्या-क्या गायब हुआ है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा।

वही इस मामले को लेकर निगम कमिश्नर लीना कोसम ने कहा कि उनकी सूची के अनुसार एक भी फाइलें चोरी नहीं हुई हैं। उन्होंने पुलिस से जांच के लिए शिकायत किया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

रायगुड़ा जंगल में मुर्गा लड़ाई का अवैध खेल,बीजापुर पुलिस ने दी दबिश



बीजापुर। जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक अंतर्गत ग्राम रायगुड़ा में संचालित अवैध मुर्गा लड़ाई पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआरियों के जमावड़े पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि मुर्गा लड़ाई की आड़ में यहां लाखों रुपये का जुआ खेला जा रहा था। इस अवैध गतिविधि में शामिल होने के लिए तेलंगाना और आंध्रप्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे हुए थे। रायगुड़ा जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से मुर्गा लड़ाई का खेल संचालित होने और वहां बड़े पैमाने पर जुआ होने की सूचना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में पुलिस टीम का गठन किया गया।

इसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से मौके पर पहुंचकर दबिश दी। पुलिस की अचानक कार्रवाई से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान मौके से लगभग 20 से 25 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई मोबाइल फोन और कारें भी जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मुर्गा लड़ाई के दौरान बड़ी रकम का दांव लगाया जा रहा था और इसमें सीमावर्ती राज्यों से पहुंचे कई जुआरी शामिल थे। पुलिस अब जब्त नकदी, मोबाइल और वाहनों की विस्तृत जानकारी जुटा रही है। वहीं इस कार्रवाई में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसकी आधिकारिक जानकारी पुलिस ने साझा नही की है। वहीं दूसरी ओर भोपालपट्टनम के सीमावर्ती क्षेत्र में बाहरी राज्यों से लोगों के पहुंचकर इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल होने और पुलिस की कार्रवाई का मामला अब चर्चा का विषय बन गया है।

दिवाली से पहले मिट्टी के दीयों की मांग बढ़ी, पौनी पसारी को लेकर पेंच



कोरबा। दीपावली से पखवाड़ाभर पहले से कुम्हार मिट्टी के दीये बनाने में जुटे हुए हैं। कोरबा शहर के साथ ही आसपास के गांवों के कुम्हार परिवार इस बार मिट्टी के दीयों की डिमांड बढ़ने से उत्साहित है और दिनरात दीये, धूपदानी, लक्ष्मी प्रतिमाएं, कलश और पूजा में उपयोग होने वाली मिट्टी की अन्य सामग्री तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बार मांग में तेजी के बीच कुम्हारों को लागत बढ़ने और मजदूरों की कमी की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

कुम्हारों के मुताबिक पिछले वर्षों में वे दीपावली के लिए करीब 2 से 3 लाख दीये तैयार करते थे। इस साल सितंबर में पीएम मोदी के जन्मदिवस और सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दीपोत्सव के कारण पहले से तैयार दीयों का स्टॉक खत्म हो गया। 17 सितंबर को शहर से गांवों तक हजारों दीप जलाए गए थे। इस आयोजन में बड़ी संख्या में मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल हुआ, जिससे कुम्हारों के पास रखा पुराना स्टॉक भी खप गया। कुम्हारों का कहना है कि दीपोत्सव के बाद से लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं। मांग पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय लगाकर दीये तैयार किए जा रहे हैं।

इस बार उत्पादन लागत में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। मिट्टी, भूसा, पैरा, लकड़ी का बुरादा और परिवहन महंगा होने के साथ मजदूरों की कमी ने लागत बढ़ा दी है। इसका सीधा असर दीयों की कीमत पर पड़ा है। पिछले साल तक थोक में 100 से 120 रुपए सैकड़ा बिकने वाले सामान्य मिट्टी के दीये अब करीब 150 से 200 रुपए सैकड़ा तक पहुंच गए हैं। हालांकि कई कुम्हार अब भी 15 से 20 रुपए प्रति दर्जन के दर पर ही दीये बेच रहे हैं। कुम्हारों का कहना है कि इस बार बाजार में मिट्टी के दीयों की मांग उत्साहजनक है, लेकिन बढ़ती लागत के कारण मेहनत के अनुपात में लाभ बनाए रखना बड़ी चुनौती बनी हुई है।दूसरी तरफ निगम की सख्ती भी इस वर्ष कुम्हारों के लिए मुसीबत बन गई है। वर्षों से कुम्हार बुधवारी बाजार के फुटपाथ पर अपना व्यवसाय करते आए हैं, लेकिन भविष्य की योजनाओं के मद्देनजर नगर पालिक निगम ने इस बार यहां दुकान लगाने पर प्रतिबंध लगाया है।बुधवारी के समक्ष आनंद बाजार में पौनी पसारी योजना के तहत बनाया गए पसेरी में कुम्हारों को व्यवसाय करने की बात निगम ने कही है, लेकिन कुम्हार वहां नहीं जाना चाहते। निगम ने पौनी पसारी योजना के तहत बनाए गए पसरा में पूरी व्यवस्था देने की बात भी कही है। निगम की दलील है कि फुटपाथ की दुकान दुर्घटनाओं का आमंत्रण देती है, यह पूरी तरह से गैरजिम्मेदारी भरा काम है। आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि पिछले साल वीआईपी रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया था, जिसमें निगम के कर्मचारी की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि वहां डिवाइडर बनाया जा रहा है। आगे गौरवपथ का प्लान है। ऐसे में दुकानदार आगे वहां बैठ ही नहीं पाएंगे। बुधवारी बाजार में पसरे को आवंटित करने की बात आयुक्त ने कही।

खैरागढ़ में जर्जर स्कूल की खामियां छिपाता प्लास्टिक कवच



खैरागढ़। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के बड़े-बड़े दावे,हर साल जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए करोड़ों का बजट, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर है।खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के वनांचल से आई ये तस्वीर शिक्षा विभाग की लापरवाही की सबसे बड़ी गवाह है। यहां एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की छत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी बच्चों पर गिर सकती है। बच्चों को बचाने के लिए शिक्षकों को छत पर पॉलीथीन बिछानी पड़ रही है।लेकिन ये जुगाड़ कितना खतरनाक है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर वनांचल ग्राम पंचायत सरईपतेरा के आश्रित ग्राम लालपुर घाट का शासकीय प्राथमिक शाला। पिछले एक साल से भवन जर्जर हालत में है। छत का प्लास्टर जगह-जगह से उखड़कर गिर चुका है, सरिया बाहर निकल आया है। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है। इसी जानलेवा छत के नीचे रोजाना 30 से ज्यादा मासूम बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं।ऐसे में यदि कोई घटना हो जाए तो परिणाम कितना भयानक होगा इसके बारे में सोचकर ही रुह कांप उठती है।

शिक्षकों, सरपंच और ग्रामीणों ने कई बार मरम्मत और नए भवन की मांग की। लेकिन सुनवाई नहीं हुई। नतीजा शिक्षकों को मजबूरन स्कूल की पक्की छत पर प्लास्टिक बिछानी पड़ीं। ये नजारा आमतौर पर झुग्गी-झोपड़ियों में दिखता है, लेकिन सरकारी स्कूल में बारिश से बचने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। इतना सब करने के बाद भी ना तो विभाग ने मरम्मत कराई और ना ही बच्चों के पढ़ने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की। वहीं जिम्मेदार अब मामला सामने आने के बाद व्यवस्था की दुहाई देते दिख रहे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

छग में मकड़ियों की दो नई प्रजातियों का पहला राज्य रिकॉर्ड

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के जैव विविधता से समृद्ध जंगलों में मकड़ियों की दो महत्वपूर्ण प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र स्थित ऋषिझरन जंगल में किए गए शोध के दौरान जाल बनाने वाली मकड़ियों (Cobweb Spiders) की दो प्रजातियां Steatoda cingulata (Thorell, 1890) और Theridula gonygaster (Simon, 1873) मिली हैं। इन दोनों प्रजातियों का छत्तीसगढ़ में पहली बार वैज्ञानिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यह अध्ययन मकड़ियों के वर्गीकरण एवं भौगोलिक वितरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विशेष बात यह है कि इन दोनों प्रजातियों के साथ इनके संबंधित वंश (Genera) Steatoda और Theridula का भी छत्तीसगढ़ में पहली बार रिकॉर्ड दर्ज किया गया है।शोध के दौरान दोनों प्रजातियों को गरियाबंद जिले के देवभोग स्थित ऋषिझरन वन क्षेत्र से हाथों द्वारा एकत्रित किया गया। यह वन क्षेत्र ओडिशा की सीमा के समीप स्थित है। इन दोनों मकड़ियों की शारीरिक बनावट भी इन्हें एक-दूसरे से अलग पहचान देती है।

खड़ी हाइवा में लगी आग अंदर सो रहा था ड्राइवर, बची जान

बालोद। बोलोद जिले के डौंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत लिमहाटोला गांव में सड़क किनारे खड़ी हाइवा में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। ट्रक के अन्दर ड्राईवर सो रहा थो जैसे ही उसे आग लगने की भनक लगी ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक, ड्राइवर ने हाइवा को सड़क किनारे खड़ा किया था। रात में वह गाड़ी में ही सो रहा था। इसी दौरान सुबह करीब 5 बजे अचानक हाइवा में आग लग गई। आग की लपटें देखकर ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। इससे उसकी जान बच गई, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना पर डॉयल 112 और डौंडी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक हाइवा पूरी तरह जल चुकी थी। फिलहाल हाइवा में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

अनजान लोगों को दी लिफ्ट सफर के दौरान आया चक्कर

डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में मदद के नाम पर भरोसा करना एक युवक को भारी पड़ गया। रास्ते में लिफ्ट मांगने वाले दो अनजान व्यक्तियों को युवक ने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिन्हें वह लिफ्ट दे रहा है, वही उसकी बाइक लेकर फरार हो जाएंगे। प्रज्ञागिरि पहुंचने के बाद युवक को अचानक चक्कर आया और वह सड़क किनारे लेट गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो दोनों व्यक्ति मौके से गायब थे। इतना ही नहीं, उसकी मोटरसाइकिल भी वहां नहीं थी। युवक ने आसपास तलाश की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उसे समझ आया कि लिफ्ट मांगकर साथ आए दोनों व्यक्ति उसकी बाइक लेकर फरार हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार घटना 30 अक्टूबर की है। डोंगरगढ़ के बधियाटोला वार्ड क्रमांक 7 निवासी 25 वर्षीय विशाल टेम्भुरकर अपनी हीरो होंडा सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी07 एफ 7262 से प्रज्ञागिरि जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में दो अज्ञात व्यक्तियों ने उससे लिफ्ट मांगी

मनेन्द्रगढ़ की 14 ग्राम पंचायतों में घर-घर संग्रहण की पहल

एमसीबी। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के गांवों में अब घरों से निकलने वाला कचरा गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर बिखरने के बजाय निर्धारित संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत विकासखंड की 14 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता ग्राही घर-घर पहुंचकर कचरा एकत्रित कर रहे हैं। इस पहल से गांवों में साफ-सफाई की व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही ग्रामीणों को कचरा निस्तारण की सुविधा भी मिल रही है। स्वच्छता ग्राहियों की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत लालपुर, मुख्तियारपारा, डगौरा, भलौर, परसगढ़ी, बौरीडांड, छिपछिपी, लाई, ताराबहरा, भौता, कछौड़, पाराडोल, बुंदेली एवं बेलबहरा में स्वच्छताग्राहियों के माध्यम से घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य संचालित किया जा रहा है।

इंग्लिश स्किल कार्यक्रम का चपले महाविद्यालय में शुभारंभ

खरसिया। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नवीन शासकीय महाविद्यालय चपले जिला रायगढ़ में इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्किल कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य एस राठिया के मार्गदर्शन एवं एम एल पटेल सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के नेतृत्व में सफलता पूर्वक हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदा की पूजन वंदन से शुरू हुआ। एमएल पटेल सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी ने कार्यक्रम की रूपरेखा उद्देश्य एवं विषय वस्तु पर विस्तृत जानकारी दी। उपस्थित छात्र-छात्राओं ने अंग्रेजी भाषा के महत्व पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए। आज के कार्यक्रम में 40 विद्यार्थियों की सहभागिता रही। महाविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रोफेसर एसके मेहर ,प्रोफेसर डॉ. एस मण्डल, प्रोफेसर डॉ. डिंपल अग्रवाल ,प्रोफेसर डॉ.प्राची थवाईत ,प्रोफेसर छाया सिदार,प्रोफेसर संगीता सिदार,प्रोफेसर प्रमिला कंवर,ग्रंथपाल जयश्री मांझी और श्री राम नारायण साहू जी ने अंग्रेजी भाषा के भविष्य एवं महत्व पर अपने-अपने विचार व्यक्त किया।

एक सपना और फिर 7 दिन पहले त्योहार मनाने की शुरू हुई अनोखी परंपरा



धमतरी। देशभर में दीपावली को लेकर जहां लोग तैयारियों में लगे हैं वहीं छत्तीसगढ़ के एक गांव में 7 दिन पहले ही ये त्योहार हो भी गया। देशभर में जहां त्योहार के दिन कई तरह की अनोखी परंपराएं निभाई जाती हैं। वहीं धमतरी के सेमरा गांव में दीपावली के साथ ही 4 प्रमुख त्योहार को तय तिथि से 7 दिन पहले ही मनाने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं और लोक आस्थाओं के बीच धमतरी जिले का सेमरा सी गांव अपनी एक अनूठी पहचान रखता है। यहां दीपावली, होली, हरियाली और पोला जैसे चार प्रमुख त्योहार सामान्य तिथि से एक सप्ताह पहले मनाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे गांव के आराध्य सिरदार देव की मान्यता जुड़ी हुई है। इस बार भी मंगलवार 3 नवंबर को गांव में दीपावली का पर्व पूरे उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। दीयों की रोशनी से घर-आंगन जगमगाए, रंगोलियों से चौखट सजी और गांव में उत्सव का माहौल नजर आया। इस अनूठी परंपरा को देखने और त्योहार में शामिल होने आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ग्रामीणों के अनुसार सिरदार देव की कहानी उनके पूर्वजों से चली आ रही है। बताया जाता है कि पुराने समय में सेमरा सी गांव छोटे-छोटे घरों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। जंगली जानवरों और अन्य बाधाओं के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी दौरान सिरदार नाम के एक व्यक्ति गांव में शिकार करने पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को जंगली जानवरों से राहत दिलाई, लेकिन इस दौरान स्वयं वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद कहा जाता है कि गांव के पुजारी को स्वप्न में सिरदार देव के निर्देश मिले। ग्रामीणों को पहले उनकी पूजा-अर्चना करने और इसके बाद ही त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई। तभी से गांव में सिरदार देव की आराधना के बाद प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। ग्रामीण इस मान्यता को गांव की सुख-शांति, सुरक्षा और समृद्धि से जोड़कर देखते हैं। गांव के लोगों की मानें तो गांव के देवता सिरदार देव हैं। सालों पहले जब गांव में विपदा आई थी, तब गांव के मुखिया को ग्राम देवता सिरदार देव सपने में आए और आदेश दिया कि हर त्योहार और पर्व सात दिन पहले मना लें। अगर ऐसा नहीं किया तो गांव में फिर से कोई न कोई विपदा जरूर आएगी। शुरू में सभी लोगों ने इस बात को नहीं माना और परंपरागत रूप से त्योहार मनाने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में संकट आने लगा। कभी बीमारी, तो कभी अकाल पड़ने लगा। तब ग्रामीणों ने सपने वाली बात का पालन करने का फैसला किया। सेमरा सी गांव की परंपरा का एक और विशेष पहलू सिरदार देव मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित होना है। यहां केवल पुरुष ही मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह व्यवस्था भी पूर्वजों से चली आ रही धार्मिक मान्यता का हिस्सा है, जिसका आज तक पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया जा रहा है। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवा पीढ़ी तक इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है।

बसोर समुदाय की महिलाओं की बदली जिंदगी



सूरजपुर। पहले भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे तो कोई कुछ कुछ भी बोल देता था, लेकिन अब अपना काम कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। टोकनी बना रहे हैं, सूपा बनाना सीख रहे हैं। भैयाथान ब्लॉक के बसोर समुदाय की कई महिलाओं का अब यही कहना है। बसोर समुदाय अनुसूचित जाति वर्ग में आता है। इनका पारंपरिक काम बांस की चीजें बनाना है। लेकिन बांस की पारंपरिक चीजों की डिमांड कम होने और बाजार नहीं मिलने के कारण बसोर लोग बांस की चीजें बनाने का काम छोड़कर दूसरा काम करने को मजबूर है। कुछ भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक के शमोली और डालबहरा गांव की बसोर समुदाय की महिलाएं सालों से भिक्षावृत्ति करने को मजबूर थीं। गरीबी, अशिक्षा और रोजगार के साधन न होने से उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों की जानकारी जुटाई और उन्हें मदद दिलाई। महिलाओं को बांस की चीजें बनाने की ट्रेनिंग दी गई। सूरजपुर जिला प्रशासन की टीम ने इन महिलाओं का सर्वे कराया, उनके साथ बातचीत की और उनकी जरूरतों को समझा। महिला राहत योजना के तहत तीन जरूरतमंद महिलाओं को चिन्हित कर 40-40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई। अब इन महिलाओं ने भिक्षावृत्ति छोड़कर आत्मनिर्भरता की राह पकड़ ली है। कोई बांस की टोकनी और सूपा बना रही है तो कोई अपनी किराना दुकान से परिवार का पेट पाल रही है। इस आर्थिक मदद से दो महिलाओं ने अपने पारंपरिक हुनर को रोजगार में बदला। प्रशासन ने सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं की बल्कि इन महिलाओं के आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज भी बनवाए और उन्हें शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा है।

संक्षिप्त समाचार

अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी राहुल गांधी को नक्सलवाद पर बहस की चुनौती



रायपुर। इन दिनों देश-प्रदेश में नेताओं का एक-दूसरे को चुनौती देने का सिलसिला शुरू हो चला है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों से कनेक्शन और देशद्रोह के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दे दी है। उनकी चुनौती को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी की बहस की चुनौती दे दी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी को नक्सलवाद के मुद्दे पर सार्वजनिक मंच पर बहस की चुनौती देते हुए कहा कि किसी भी जगह, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी वक्त डिबेट को तैयार हूं। आपकी पार्टी के कुछ नेता नक्सली को अपना हीरो बताते हैं। जिन्होंने झीरम घाटी में आपके ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हत्या की थी। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस दिखाएंगे?

नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए प्रदेश चुनाव टोली की घोषणा की है। गठित चुनाव टोली मे संतोष पाण्डेय - प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद, अखिलेश सोनी - भाजपा प्रदेश महामंत्री, भूपेन्द्र सवन्नी - अध्यक्ष राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), सौरभ सिंह - अध्यक्ष खनिज विकास निगम, किशोर राय - प्रदेश संयोजक नगरीय निकाय प्रकोष्ठ, प्रफुल विश्वकर्मा - अध्यक्ष लौह शिल्पकार विकास बोर्ड और पंकज कुमार झा - मीडिया सलाहकार को शामिल किया गया है। टोली के पदेन सदस्य के रूप में सुनील पिल्लई - भाजपा आईटी सेल प्रदेश संयोजक, मितुल कोठारी - भाजपा सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक और हेमंत पाणिग्रही - भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक शामिल किया गया है। इसी प्रकार आगामी नगरीय निकाय चुनावों और उपचुनाव के मद्देनजर प्रभारियों एवं सह-प्रभारियों की सूची घोषित की गई है = रायगढ़ जिला की नगर पंचायत तमनार के लिए लखनलाल साहू को प्रभारी और श्रीमती संयोगिता सिंह जूदेव व जोगेश लाम्बा को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। धमतरी जिला की नगर पंचायत बड़ी करेली में शशि पवार को प्रभारी और अरूण सार्वा व श्रीमती ज्योति चंद्राकर सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला की नगर पंचायत बिलाईगढ़ में केवल अध्यक्ष पद के उपचुनाव हेतु केदार गुप्ता को प्रभारी और चन्द्रकुमार पटेल व श्रीमती अल्का चंद्राकर को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।

शाह का संकल्प, बस्तर जैसे नक्सल मुक्त हुआ वैसे ही देश नशा मुक्त होगा : अनुराग



रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नशा मुक्त भारत के संकल्प का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने स्वागत करते हुए कहा कि शाह ने स्पष्ट लक्ष्य रखा है कि 2029 तक देश को नशा मुक्त बनाना है। जिस दृढ़ इच्छाशक्ति से केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है, उसी प्रकार देश को नशा मुक्त करने का लक्ष्य भी अवश्य पूरा होगा। अग्रवाल ने कहा कि नक्सलवाद की तरह ही नशा भी युवा पीढ़ी और देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। नक्सलवाद बंदूक से मारता है और नशा धीरे-धीरे पूरे परिवार और समाज को खोखला करता है। भाजपा सरकार नक्सलवाद पर जैसे सर्जिकल प्रहार कर रही है, वैसे ही नारकोटिक्स के पूरे नेटवर्क पर भी प्रहार किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में एनसीबी और सभी एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत, विकसित भारत के संकल्प की पहली शर्त है और 2029 तक यह लक्ष्य पूरा होकर रहेगा।

राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा अब 3 जनवरी



रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा राष्ट्रीय साधन सह-प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2026-27 की तिथि में संशोधन किया गया है। अब यह परीक्षा 12 दिसंबर के स्थान पर 3 जनवरी रविवार को प्रदेश के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अधिसूचना के तहत 12 एवं 13 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय साधन सह- प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का आयोजन अब 3 जनवरी को निर्धारित परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। इस संबंध में मंडल द्वारा संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को संशोधित परीक्षा तिथि की जानकारी परीक्षार्थियों तक पहुंचाने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

महादेव सट्टा ऐप केस : सौरभ चंद्राकर को 8 दिन की सीबीआई रिमांड

■ अब सीबीआई मुख्यालय दिल्ली में होगी पूछताछ



रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने सौरभ चंद्राकर की 8 दिन की कस्टोडियल रिमांड मंजूर कर दी है। इसके साथ ही सीबीआई को उसे दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय ले जाकर पूछताछ करने की अनुमति भी मिल गई है। अब सौरभ से दिल्ली में सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी।

कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी। एजेंसी सौरभ चंद्राकर से महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप के संचालन, कथित सट्टेबाजी नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ कर सकती है।

सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। इसके बाद सीबीआई उसे दिल्ली से रायपुर लेकर पहुंची और बुधवार को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी की वैधता और प्रत्यर्पण की शर्तों को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं, सीबीआई ने रिमांड की मांग करते हुए पूछताछ की जरूरत बताई थी।

अब अदालत से रिमांड और दिल्ली मुख्यालय ले जाने की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई की टीम उससे विस्तार से पूछताछ करेगी। सीबीआई मुख्यालय में यह पूछताछ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जाएगी। कोर्ट ने पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर को शाम के समय अपने वकील से मुलाकात करने की अनुमति भी दी है।

करीब 6,000 करोड़ रुपये के कथित महादेव सट्टेबाजी नेटवर्क की जांच में सौरभ चंद्राकर की पूछताछ अहम मानी जा रही है। जांच एजेंसियों के सामने नेटवर्क के संचालन, पैसों के लेन-देन, हवाला के जरिए रकम भेजने और कथित संरक्षण राशि जैसे कई पहलू हैं।

सौरभ से पूछताछ में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, विदेशों में संचालित गतिविधियों और आर्थिक लेन-देन को लेकर अहम जानकारियां सामने आने की संभावना है। हालांकि, पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जांच में कौन-कौन से नए तथ्य सामने आते हैं।

सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में होंगे बड़े खुलासे, कई लोगों के नाम आएंगे सामने : सीएम साय



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को जशपुर में आयोजित लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले कई मुद्दों पर सीएम ने बयान दिया। सौरभ चंद्राकर की पेशी पर सीएम साय ने कहा, महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को विदेश से भारत लाया गया है। पूछताछ में कई लोगों के नाम सामने आएंगे।

अमित जोगी द्वारा सौरभ चंद्राकर को हीरो बताए जाने पर सीएम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह उनकी सोच का परिणाम है, जैसी उनकी सोच है उसी के अनुरूप वे अपनी क्वालिटी बता रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों से है।

सीएम साय ने कहा, अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की और देश में इमरजेंसी लगाई। गैर-कांग्रेसी नेताओं को जेल में डालने का काम किया। मीडिया की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास किया। जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को धारा 356 का दुरुपयोग कर बर्खास्त किया। लोकतंत्र की बात कांग्रेस करती है तो हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस हारती है तो संवैधानिक संस्थाओं पर ठीकरा फोड़ती है और जीतती है तो इसे जनता की जीत बताती है। जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है।

पाप का घड़ा फूटा तो सट्टे के अदृश्य आका बेनकाब होने के डर से काँप रहे हैं : भाजपा



रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने महादेव सट्टा एप के मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं द्वारा जाँच एजेंसियों पर उठाए जा रहे सवालों पर जोरदार पलटवार किया है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि अपनी सरकार के समय जिस काले कारोबार को फलने-फूलने का मौका दिया गया, आज जब कानून का शिकंजा कस रहा है तो कांग्रेस नेता जनता का ध्यान भटकाने और विक्टिम कार्ड खेलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल 72 एफआईआर दर्ज करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यदि कार्रवाई हो रही थी तो सट्टे का सिंडिकेट लगातार बढ़ता कैसे गया? एफआईआर केवल जनता की आँखों में धूल झोंकने के लिए थी, जबकि पर्दे के पीछे से मुख्य आरोपियों को सुरक्षित रास्ता और अभयदान दिया जा रहा था। डॉ. मिश्रा ने बघेल से सवाल कर पूछा है कि सट्टे का असली मालिक कौन है? दुबई से लेकर रायपुर तक फैले इस सिंडिकेट के तार किसके संरक्षण में थे, यह जनता जानती है। मुख्य आरोपी की रिमाण्ड से जल्द ही सत्ता के गलियारों में बैठे असली चेहरे बेनकाब होंगे।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संधियों और प्रक्रियाओं को पूरा करके अपराधी को भारत लाना मोदी सरकार और वर्तमान राज्य सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति का परिणाम है। जिस अपराधी पर कांग्रेस सरकार 5 सालों में हाथ नहीं डाल सकी, उसे आज कानून के कठघरे में खड़ा देख कांग्रेस में घबराहट और हताशा है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि सीबीआई और ईडी जैसी जाँच एजेंसियाँ पूरी तरह स्वतंत्र और साक्ष्यों के आधार पर काम करती हैं। जाँच की आँच जैसे-जैसे ऊपर बैठे पॉवर सेंटर्स तक पहुँचेगी, वैसे-वैसे कांग्रेस नेताओं का डर और बौखलाहट और बढ़ेगी। डॉ. मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्वाभिमानी जनता भूली नहीं है कि किस तरह प्रदेश को सट्टेबाजों का सेफ हेवन बना दिया गया था। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी सुपर बॉस को बख्शा नहीं जाएगा। पाप का घड़ा भर चुका है और अब कानून अपना काम कर रहा है।

सेंट विंसेंट पैलोटी महाविद्यालय में लीडरशिप फॉर एक्सीलेंस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन



रायपुर। सेंट विंसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर द्वारा प्राइवेट कॉलेजेस प्रिंसिपल वेलफेयर एसोसिएशन (निजी महाविद्यालय प्राचार्य कल्याण संघ) के तत्वावधान में लीडरशिप फॉर एक्सीलेंस एंपावरिंग प्रिंसिपल्स फॉर विकसित भारत 2047 विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी नेतृत्व, संस्थागत विकास एवं शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्राचार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार-विमर्श करना था।

सेंट विंसेंट पैलोटी महाविद्यालय में लीडरशिप फॉर एक्सीलेंस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रो. संजीव प्रशार, निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान , रायपुर उपस्थित रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. कुलदीप दुबे ने अपने स्वागत उद्बोधन में सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व ही शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर कर सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में उच्च शिक्षण संस्थानों एवं उनके प्राचार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सकारात्मक दृष्टिकोण एवं सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

निजी महाविद्यालय प्राचार्य कल्याण संघ के अध्यक्ष डॉ. मेघेष तिवारी एवं सचिव डॉ. देवाशीष मुखर्जी ने बताया कि वर्तमान बदलते शैक्षणिक परिवेश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के नेतृत्वकर्ताओं का सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में सहभागिता के लिए शहर के लगभग 30 महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने अपनी सहमति प्रदान की है।

मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रो. संजीव प्रशार ने अपने उद्बोधन में शैक्षणिक संस्थानों के विकास में दूरदर्शी नेतृत्व, नवाचार एवं प्रभावी प्रबंधन के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा एवं मूल्यपरक शिक्षा की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सांस्कृतिक चेतना का विकास भी होना चाहिए। उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपराओं एवं अपनी जड़ों से जुड़ाव बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

पुराने मतदाता भी भर सकते हैं फॉर्म-6 चुनाव आयोग ने दूर किया संशय



रायपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं होने से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों का नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन नई प्रारूप मतदाता सूची में छूट गया है वे भी दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कोई दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आया था कि कई पूर्व पंजीकृत मतदाता फॉर्म-6 भरने से झिझक रहे हैं। इसकी वजह फॉर्म में पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने संबंधी घोषणा है। लोगों को आशंका थी कि पहले से पंजीकृत होने के बावजूद यह घोषणा करने पर उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

इस संशय को दूर करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी नागरिक का नाम वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है तो अंतिम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उसे नए सिरे से फॉर्म-6 जमा करना होगा। पूर्व में मतदाता होने के बावजूद फॉर्म-6 भरना गलत या झूठी घोषणा नहीं माना जाएगा।

आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय के 14 अक्टूबर 2026 के फैसले का भी संदर्भ दिया है। याचिका संख्या W.P. (C) No. 14955/2026 (निलोत्पल दत्ता एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य) में अदालत ने भी स्पष्ट किया था कि इस स्थिति में गलत घोषणा को लेकर आशंका निराधार है और संबंधित आवेदक नियमानुसार फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केवल इस आधार पर किसी आवेदक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं की जाए कि उसका नाम पहले की मतदाता सूची में दर्ज था। हालांकि, आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत न हो। आवेदन निर्धारित कानूनी नियमों के अनुरूप होना भी जरूरी है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचें। यदि नाम सूची में नहीं मिलता है तो बिना किसी डर या संकोच के समय रहते फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।

राहुल गांधी के डिबेट चैलेंज पर मंत्री ओपी चौधरी का पलटवार

■ कहा- पॉलिटिकल हाइट बढ़ाने के लिए चिल्ला रहे



रायपुर। राहुल गांधी के डिबेट चैलेंज और स्क्रैचपर अमित शाह के लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने के बयान पर मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता राहुल गांधी को नकार चुकी है और उन्हें 100 से अधिक बार पराजय का स्वाद चखा चुकी है। राहुल गांधी अपनी राजनीतिक हाइट बढ़ाने के लिए डिबेट की बात कर रहे हैं।

ओपी चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें जॉइंट पार्लियामेंट या विशेष सत्र में चर्चा का प्रस्ताव दिया है। लेकिन वह सत्र से दूर भागेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी पॉलिटिकल हाइट बढ़ाने के लिए चिल्ला रहे हैं।

मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि 'पीपल सिटी' के रूप में विकसित करने की तैयारी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को 'विकसित भारत संकल्प पीपल वन' का लोकार्पण किया था। उन्होंने 5 लाख पीपल के पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने बताया कि पहले एक लाख पीपल के पेड़ लगाने का लक्ष्य था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।

रायगढ़ में एक कॉलेज में वंदे मातरम का पूरा गायन नहीं होने के मामले में नोटिस जारी किए जाने पर भी वित्त मंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में वंदे मातरम का अधूरा गायन हुआ था, जिसके बाद गायन पूरा किया गया। इस मामले में कलेक्टर ने प्रशासनिक सख्ती बढ़ाते हुए नोटिस जारी किया है। उन्होंने लोगों से वंदे मातरम एक्ट का पालन करते हुए व्यवहार करने की अपील की।

बस्तर के विकास को लेकर ओपी चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को राज्य बनाकर बड़ी सौगात दी थी। इसके लिए छत्तीसगढ़वासी उनके आभारी हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद बस्तर में विकास की नई संभावनाएं उभरकर सामने आई हैं। आने वाले समय में बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होगा और छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के हित में राज्य निर्माण का फैसला नहीं लिया।

'ज्ञानु और जानू' वीडियो पर मामला दर्ज होते ही फरार हुए अमित जोगी

■ पुलिस ने घर के बाहर लगाया नोटिस



रायपुर। विवादास्पद ज्ञानु और जानू वीडियो पर भाजपा नेताओं की शिकायत पर रायपुर पुलिस के मामला दर्ज करते ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी गायब हो गए हैं। ऐसे में मामले में पूछताछ के लिए सिविल लाइन पुलिस ने जोगी निवास में अमित जोगी के नाम से नोटिस चस्पा कर पूछताछ के लिए एक दिन में थाने हाजिर होने के लिए निर्देश दिया है।

सिविल लाइन पुलिस ने जोगी निवास पर अमित जोगी के नाम से चस्पा नोटिस में लिखा है कि थाने में धारा 196, 352, 353(2), 356 (2) बीएनएस एवं आईटी एक्ट के तहत 3 नवंबर को दर्ज मामले की जांच में तथ्यों और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिए युक्तियुक्त आधार पाया गया हैं, जिसके लिए आपको नोटिस प्राप्ति के एक दिवस के भीतर थाना में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजित जोगी के बेटे अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया था, जिसमें पीएम और सीईसी का मुखौटा पहने दो लोग दिख रहे थे। इसके बाद उनकी सांकेतिक शादी करवाई। बाद में हनीमून के नाम पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

अमित जोगी के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर घोर आलोचना होने लगी। साथ ही उनकी मानसिकता और सस्ती राजनीति पर सवाल उठाने लगे। विवाद बढ़ता देखकर अमित जोगी ने अपना पोस्ट सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा कि एक रेखा जिसे मैं पार नहीं करना चाहता। अब पोस्ट हटा दी गई। उन्होंने लिखा कि हनीमून पोस्ट के संदर्भ में, आज सुबह मुझे एहसास हुआ कि जो संदेश मैं देना चाहता था, वह मेरे विश्वास के अनुसार आज भी वैध है, लेकिन उसे जिस तरीके से दिया गया, वह आदर्श नहीं था।

इधर पुलिस कर रही तलाश, उधर गुजराती थाली का आनंद ले रहे अमित जोगी!



रायपुर। 'ज्ञानु और जानू' वीडियो के साथ वायरल हो रहे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता अमित जोगी को एक तरफ मामले में पूछताछ के लिए रायपुर पुलिस तलाश कर रही है, वहीं प्रदेश में कोसो दूर गुजरात के सूरत शहर में अमित जोगी गुजराती थाली का आनंद लेते हुए, फोटो सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं।

बता दें कथित आपत्तिजनक वीडियो के सोशल मीडिया में आने के बाद भाजपा के नेताओं ने जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। इस पर रायपुर की सिविल लाइंस पुलिस ने धारा 196, 352, 353(2), 356 (2) बीएनएस एवं आईटी एक्ट के तहत मामले दर्ज कर जांच में जुट गई है। मामले में पूछताछ में शामिल होने के लिए जोगी निवास के बाहर नोटिस चस्पा भी कर दिया है।

सोशल मीडिया में बवाल कटने के बाद हालांकि, अमित जोगी ने माफी मांगते हुए अपना पोस्ट डिलिट कर दिया है, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। पुलिस मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। लेकिन उनके रायपुर में नहीं होने से फरार होने की बात तेजी से फैल रही है।

हालांकि, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) प्रदेश संगठन महामंत्री निलेश चौहान ने जारी एक बयान में कहा कि अमित जोगी जी के फरार होने की खबरें भ्रामक हैं। उनका 2 नवंबर से 8 नवंबर तक निजी कार्यक्रम के तहत प्रदेश से बाहर रहने का दौरा पहले से निधारित था।

दुर्ग-बरौनी पूजा स्पेशल ट्रेन हुई रवाना

रायपुर-बिलासपुर। दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दुर्ग और बरौनी के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया जो प्रत्येक बुधवार रायपुर और प्रत्येक गुरुवार को बरौनी से रवाना होगी जिसके तहत आज दुर्ग रेलवे स्टेशन से सुबह 10.30 बजे रवाना हुई। यह ट्रेन तीन-तीन फेरे लगाएगी और इस ट्रेन से छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जाने वाले यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलने में मदद मिलेगी।

गाड़ी संख्या 08755 दुर्ग-बरौनी पूजा स्पेशल प्रत्येक बुधवार को चलेगी और आज सुबह यह ट्रेन दुर्ग से सुबह 10.30 बजे रवाना हुई और रायपुर रेलवे स्टेशन में 11.15 बजे पहुंची कर 11.20 बजे यहां से रवाना हुई। भाटापारा में 12.12 बजे पहुंचकर 12.14 बजे और बिलासपुर में दोपहर 1.15 बजे पहुंचकर 1.25 बजे रवाना होगी। इसके बाद चांपा में 2.14 बजे और रायगढ़ में 3.08 बजे पहुंचेगी। अगले दिन सुबह 11 बजे बरौनी पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन 11 और 18 नवंबर को चलेगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 08756 बरौनी-दुर्ग स्पेशल प्रत्येक गुरुवार 5, 12 और 19 नवंबर को दोपहर 2 बजे बरौनी से रवाना होगी। रायगढ़ में अगले दिन 12.25 बजे, चांपा में 1.35 बजे और बिलासपुर में 3.55 बजे पहुंचेगी।

कर्नाटक में कांग्रेस क्यों हारी एमएलसी चुनाव?

राहुल कुमार

कर्नाटक में विधान परिषद की चार सीटों पर हार के बाद कांग्रेस के भीतर जवाबदेही को लेकर आवाज उठने लगी है। पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री केएन राजन्ना ने मंगलवार को कहा कि स्टिंग ऑपरेशन विवाद भी हालिया चुनाव में कांग्रेस की हार की एक वजह हो सकता है। उन्होंने दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 35 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 26 कांग्रेस विधायकों से हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। राजन्ना ने कहा कि इस जिम्मेदारी में वह खुद भी शामिल हैं। कांग्रेस को विधान परिषद की चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इन चुनावों के नतीजे 28 अक्तूबर को घोषित हुए थे। राजन्ना ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 35 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के 26 विधायक होने के बावजूद पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी। ऐसे में सभी को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, इन 35 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के 26 विधायक होने के बावजूद हम जीत नहीं सके। अगर 26 विधायकों के रहते हुए भी हम चुनाव नहीं जीत पाए तो हम सभी 26 लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें मुझे भी शामिल किया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री राजन्ना ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन विवाद का मतदाताओं पर असर पड़ा होगा। उनके मुताबिक, चुनाव में मतदान करने वाले लोग शिक्षित थे और वे हर मुद्दे का खुद आकलन करते हैं। उन्हें अपने वोट के जरिए नाराजगी जाहिर करने का भी मौका मिला। उन्होंने कहा, इसका निश्चित रूप से असर पड़ा होगा। क्योंकि वोट देने वाले सभी लोग शिक्षित हैं। वे हर मुद्दे का खुद आकलन और विश्लेषण करते हैं। उन्हें अपने वोट के जरिए नाराजगी जाहिर करने का भी मौका मिला। मेरा मानना है कि ऐसा ही हुआ है। राजन्ना ने स्टिंग ऑपरेशन की उचित जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि जांच उच्च स्तर की हो या निचले स्तर की, सबसे जरूरी यह है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। राजन्ना ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की हाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि सिद्धारमैया ने स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े घटनाक्रम, पार्टी पर इसके नकारात्मक असर और अपनी व्यक्तिगत छवि को हुए नुकसान के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा, मैंने उनकी मुलाकात से पहले उनसे बात की थी। मुलाकात के बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई है। मैं आज उनसे बात करूंगा। राजन्ना ने यह भी कहा कि चुनाव नहीं लड़ने और उसके बाद प्रचार नहीं करने को लेकर दिए गए विरोधाभासी बयानों का पार्टी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इन सभी घटनाक्रमों का पार्टी पर बुरा प्रभाव पड़ना तय है। पूर्व मंत्री ने कहा कि पार्टी के सभी विधायकों की जिम्मेदारी है कि वे संगठन की ओर से लिए गए फैसलों को लागू करें। अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।उन्होंने कहा, अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं तो हम सभी ने गलती की है। इस गलती के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। कांग्रेस के भीतर स्टिंग ऑपरेशन को लेकर विवाद तब बढ़ा जब पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को बदनाम करने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता कृपा अल्वा इसके पीछे थीं। इसके बाद पार्टी ने उन्हें छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। कांग्रेस ने सिद्धारमैया के खिलाफ इस अभियान के लिए जनता दल (सेक्युलर) को जिम्मेदार ठहराया है।

इंडी गठबंधन की महारैली के सियासी निहितार्थ

कमलेश पांडे



दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को आयोजित इंडी (INDIA) गठबंधन की महारैली केवल एक राजनीतिक सभा नहीं थी, बल्कि यह विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर उठाए जा रहे सवालों को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने का एक और बृहत प्रयास था।

वोट बचाओ, देश बचाओ और चलो दिल्ली के संदेश के साथ आयोजित इस रैली में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, सीपीआई एम, सीपीआई एमएल सहित लगभग 20 विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। अधिकांश नेताओं ने गर्मजोशी पूर्वक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई और निज अनुभवजन्य आरोप लगाए। सबसे अंत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संतुलित भाषण देते हुए एक परिपक्व नेता प्रतिपक्ष का परिचय दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए खट्टा मीठा आरोप लगाए, जिसमें ताना और दुलार दोनों शामिल रहा।

इस घटनाक्रम को समझने के लिए अग्रांकित सात महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है-

पहला, चुनाव आयोग और एसआईआर को विपक्ष ने बनाया मुख्य राजनीतिक मुद्दा: रैली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि विपक्ष ने अपनी लड़ाई को केवल केंद्र सरकार के विरोध तक सीमित न रखकर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जोड़ने की कोशिश की। विपक्ष के प्रमुख आरोप हैं कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी से मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है।राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। इसका राजनीतिक निहितार्थ यह है कि विपक्ष चुनावी निष्पक्षता को अपनी साझा राजनीतिक लड़ाई का आधार बनाना चाहता है। वह मतदाता सूची के विवाद को लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों के व्यापक सवाल से जोड़ रहा है। हालांकि, विपक्ष के आरोपों और चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बीच वास्तविक स्थिति का निर्धारण दस्तावेजों, संबंधित मतदाता आंकड़ों और कानूनी जांच के आधार पर ही होना चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर के आदेशों को वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप बताया गया है।

दूसरा, विपक्षी एकजुटता का सार्वजनिक प्रदर्शन, लेकिन नेतृत्व का सवाल बरकरार: इस महारैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं की मौजूदगी महत्वपूर्ण रही। इससे विपक्ष ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रखने वाले दल राष्ट्रीय मुद्दों पर एक मंच पर आ सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी कायम है- एक, गठबंधन का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में होगा? दो, क्या कांग्रेस और क्षेत्रीय दल एक-दूसरे के राजनीतिक हितों को पर्याप्त जगह देंगे? तीन, क्या विपक्ष साझा मुद्दों पर आंदोलन के साथ-साथ साझा नीतिगत कार्यक्रम भी बना पाएगा? चार, क्या चुनाव के समय सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार चयन पर सहमति कायम रह सकेगी? इसका सियासी निहितार्थ यह है कि प्रमुख विपक्षी नेताओं द्वारा एक मंच पर नेताओं का खड़ा होना और एक साझा राजनीतिक संगठन की तरह काम करना दो अलग-अलग बातें हैं। महारैली ने पहले पहलू को प्रदर्शित किया, जबकि दूसरे की परीक्षा आगे होगी।

तीसरा, कांग्रेस की राष्ट्रीय भूमिका और राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति: रैली के आयोजन में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका रही। खड़गे और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग तथा केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज को सामने रखा। राहुल गांधी ने नागरिकों के मताधिकार को धर्म और राजनीतिक पहचान से ऊपर रखने की बात कही। दूसरी ओर, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने अपने-अपने राज्यों से जुड़े एसआईआर के सवालों को भी उठाया। इस घटनाक्रम के तीन राजनीतिक पहलू हैं- एक, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गतिविधियों का साझा मंच उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। दो, राहुल गांधी के लिए लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता का मुद्दा उनकी राष्ट्रीय राजनीतिक संवाद शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। तीन, क्षेत्रीय दल इस मंच के माध्यम से अपने राज्य के राजनीतिक मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श में जगह दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय भूमिका और गठबंधन के भीतर अन्य दलों की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी रहेगी।

चौथा, ममता, अखिलेश और अन्य क्षेत्रीय नेताओं के अपने राजनीतिक संदेश: महारैली में सभी नेताओं का भाषण एक जैसा नहीं था। जहां अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची और कथित नाम कटने के मुद्दे को उठाया। वहीं, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के प्रभाव का विरोध किया। उधर, तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में महाभारत के शकुनि का संदर्भ दिया और पूछा कि आज के कौन है? इसके पीछे उनका गहरा दर्द यह है कि बिहार के दिग्गज समाजवादी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनि चौधरी के पुत्र और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर तुषारापात कर दिया। वहीं, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक भागीदारी के सवाल उठाए। इससे स्पष्ट होता है कि गठबंधन का साझा मंच होने के बावजूद उसके प्रत्येक घटक दल की अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताएं हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में मतदाता सूची, सामाजिक समीकरण और चुनावी प्रतिस्पर्धा के अलग-अलग संदर्भ हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नारा सभी राज्यों में समान राजनीतिक अर्थ नहीं रखता।

पांचवां, भाजपा और विपक्ष के बीच टकराव अब चुनावी संस्थाओं के सवाल तक पहुंचा: इस रैली के बाद राजनीतिक बहस का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी सामने आया कि भाजपा और विपक्ष चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक-दूसरे के विरुद्ध अलग-अलग राजनीतिक दावे पेश कर रहे हैं। जहां भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की जवाबदेही पर सवाल उठाना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। दिलचस्प बात यह है कि 1 नवंबर को ही दिल्ली के हरिनगर में भाजपा नेता हरदीप सिंह पूरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों के पीड़ितों के न्याय से जुड़ा अपना विरोध मार्च भी आयोजित किया। इससे रैली के साथ एक अलग राजनीतिक और ऐतिहासिक विवाद भी जुड़ गया। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक विमर्श केवल एसआईआर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें 1984 की त्रासदी, न्याय, राजनीतिक जवाबदेही और विपक्ष की तारीख के चयन जैसे सवाल भी शामिल हो गए।

छठा, क्या महारैली विपक्ष को जनांदोलन में बदलने की क्षमता रखती है?: किसी राजनीतिक रैली की सफलता का आकलन केवल भीड़ के आकार से नहीं किया जा सकता। असली कसौटी यह है कि उसका संदेश कितनी दूर तक पहुंचता है और उसके बाद संगठनात्मक स्तर पर क्या कार्रवाई होती है। इस दृष्टि से विपक्ष के सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं:-

एक, मतदाता सूची से जुड़े आरोपों को प्रमाणों के साथ जनता के सामने रखना, क्योंकि घुसपैठियों को निकालने, दो जगहों के वोटर लिस्ट में शामिल लोगों को हटाने के फैसले को कांग्रेस व उसके समर्थक दल नाजायज़ नहीं ठहरा सकते हैं। दो, जिन मतदाताओं के नाम छूटने की शिकायत है, उनके मामलों का तथ्यात्मक समाधान कराना होगा। तीन, चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आपत्तियों को संवैधानिक और कानूनी तरीके से उठाना होगा। चार, साझा राजनीतिक मुद्दों के साथ रोजगार, महंगाई, किसानों, युवाओं और आर्थिक विकास जैसे विषयों पर भी स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। पांच, गठबंधन के भीतर नेतृत्व और सीटों के बंटवारे पर व्यावहारिक सहमति बनाना होगा। छह, यह भी ध्यान रखना होगा कि रैली में उपस्थिति के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक दावे और प्रतिदावे सामने आए हैं। इसलिए भीड़ के आधार पर देशव्यापी जनसमर्थन का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। सातवां, इस महारैली से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के सामने क्या सवाल खड़े हुए?: इस घटनाक्रम ने तीन संस्थागत प्रश्नों को चर्चा में ला दिया है: एक, एसआईआर में पारदर्शिता कितनी है? और प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहे। दो, चुनाव आयोग की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित हो? और चुनावी संस्था पर जनता का विश्वास बना रहे।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय



22. नागार्जुन का शून्यवाद

गतांक से आगे...

बहुत दिन न केवल पाश्चात्य जगत् में प्रत्युत पिछले युग के वैदिक दार्शनिक सम्प्रदायों में भी ऐसा ही समझ लिया गया था। परन्तु एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि शून्यवाद-महायान इस प्रकार के सर्वसंहारक निषेध को लेकर प्रवृत्त हुआ तो, उस में वह ज्वलन्त सजीव धर्म-भावना कहां से आ गयी जिससे बौद्ध धर्म मध्य एशिया, चीन, जापान, मङ्गोलिया और कोरिया तक छा गया, जिस के प्रभाव से आत्मोत्सर्ग के हृदयस्पर्शी दृष्टान्तों से बौद्ध अवदान साहित्य ओत प्रोत हो रहा है जिस की प्रेरणा से प्रत्येक बुद्ध की जगह बोधिसत्त्व के आर्दश ने ली और हीनयान के निर्वाण प्राप्त अभावात्मक बुद्ध ने गान्धार कला में निरन्तर प्रेरणा और स्फूर्ति देने वाला सजीब मूर्तत आकार ग्रहण किया।

इस प्रश्न का उत्तर श्चेरबात्स्की के समान पाश्चात्य मनीषियों ने दिया जिन्होंने शून्यवाद के रहस्य को समझा । शून्यवाद का सिद्धान्त केवल निषेधात्मक नहीं है। सारे दृश्यमान जगत् को परस्पर सापेक्ष और नि:स्वभाव शून्य बताने वाला शून्यवाद एक निरपेक्ष (Absolute) तत्त्व की ओर निर्देश करता है।

महायान शून्यवाद के अनुसार यह जगत् नि:स्वभाव है शून्य है इस का अर्थ यह है कि इसका यथार्थ तत्त्व शून्य है, वह शून्य ही निरपेक्ष परम और यथार्थ सत्य है। वह शून्य ही निर्वाण या बुद्ध के रूप में है। शून्यवादी महायान के मत में बुद्ध निर्वाण या शुन्य यह सत्र उसी प्रकार पर्यायवाची शब्द हैं जिस प्रकार अद्वैतवाद वेदान्ती के मत में ब्रह्म मोक्ष ब्रह्मज्ञान आदि पर्याय-वाची शब्द हैं। वेदान्ती का निरपेक्ष तत्त्व (Absolute) ब्रह्म एक स्थिर नित्य द्रव्य के रूप में है, महायान अपने निरपेक्ष तत्त्व का उस प्रकार का निरूपण नहीं करता, परन्तु निरपेक्ष तत्त्व को दोनों ही समान रूप से मानते हैं।

क्रमश:...

चित्तरंजन दास



चित्तरंजन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील तथा पत्रकार थे। उनको सम्मान पूर्वक 'देशबंधु' कहा जाता था। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता के साथ-साथ वो एक सफल विधि-शास्त्री भी थे। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान उन्होंने 'अलीपुर षड़यंत्र काण्ड' (1908) के अभियुक्त अरविन्द घोष का बचाव किया था। कई और राष्ट्रवादियों और देशभक्तों की तरह इन्होंने भी 'असहयोग आंदोलन' के अवसर पर अपनी वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल को दे डाली। कांग्रेस के अन्दर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। जब कांग्रेस ने इनके 'कौंसिल एंट्री' प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया तब इन्होने 'स्वराज पार्टी' की स्थापना की।

चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर, 1870 को कोलकाता में हुआ था। उनका ताल्लुक ढाका के बिक्रमपुर के तेलिरबाग के प्रसिद्ध दास परिवार से था। उनके पिता भुबन मोहन दास कोलकाता उच्च न्यायालय में एक जाने माने वकील थे। ब्रह्म समाज के एक कट्टर समर्थक देशबंधु अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और पत्रकारीय दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। चित्तरंजन दास कलकत्ता उच्च न्यायालय के विख्यात वक़ील थे, जिन्होंने अलीपुर बम केस में अरविन्द घोष की पैरवी की थी।

चित्तरंजन दास ने अपनी चलती हुई वकालत छोड़कर गांधीजी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पूर्णतया राजनीति में आ गए। उन्होंने विलासी जीवन व्यतीत करना छोड़ दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए सारे देश का भ्रमण किया। उन्होंने अपनी समस्त सम्पत्ति और विशाल प्रासाद राष्ट्रीय हित में समर्पण कर दिया। वे कलकत्ता के नगर प्रमुख निर्वाचित हुए। उनके साथ सुभाषचन्द्र बोस कलकत्ता निगम के मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त हुए। इस प्रकार श्री दास ने कलकत्ता निगम को यूरोपीय नियंत्रण से मुक्त किया और निगम साधनों को कलकत्ता के भारतीय नागरिकों के हित के लिए उन्हें नौकरियों में अधिक जगह देकर हिन्दू-मुस्लिम मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया।

बंगाल और बम्बई की धारासभाओं में तो यह इतनी शक्तिशाली हो गई कि वहाँ द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिमंडल तक का बनना कठिन हो गया। श्री दास के नेतृत्व में स्वराज्य पार्टी ने देश में इतना अधिक प्रभाव बढ़ा लिया कि तत्कालीन भारतमंत्री लार्ड बर्केनहैड के लिए भारत में सांविधानिक सुधारों के लिए चित्तरंजन दास से कोई न कोई समझौता करना ज़रूरी हो गया लेकिन दुर्भाग्यवश अधिक परिश्रम करने और जेल जीवन की कठिनाइयों को न सह सकने के कारण श्री चित्तरंजन दास बीमार पड़ गए और 16 जून, 1925 ई. को उनका निधन हो गया।

चित्तरंजन दास की मृत्यु के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार से वार्ता की बात समाप्त हो गई और भारतीय स्वाधीनता की समस्या के शान्तिमय समाधान का अवसर नष्ट हो गया। चित्तरंजन दास के निधन का शोक संम्पूर्ण देश में मनाया गया। सारे देशवासी उन्हें प्यार से देशबंधु कहते थे।

ट्रंप-नेतन्याहू की ईरान को खत्म करने का प्लान!

अभिनय आकाश

अमेरिकी मीडिया हस्ती और राजनीतिक टिप्पणीकार टकर कार्लसन ने दावा किया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के खिलाफ परमाणु हमला करने का दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वाशिंगटन कुछ ही दिनों के भीतर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कोई फैसला ले सकता है। कार्लसन ने एक विस्तृत पोस्ट में लिखा है कि ये हथियार पहाड़ की ग्रेनाइट चट्टानों को भेदकर उन भूमिगत सुरंगों तक पहुंच सकते हैं, जहां कथित तौर पर परमाणु सामग्री को समृद्ध (एनरिच) करने का काम चल रहा है। कार्लसन ने लिखा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में ट्रंप प्रशासन कुछ ही दिनों में ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है। उन्होंने आगे दावा किया कि नेतन्याहू इस तरह के अभियान के लिए जोर दे रहे हैं। उन्होंने एक अज्ञात सूत्र के हवाले से कहा बीबी (नेतन्याहू) इस बारे में ट्रंप को रोज फोन करते हैं। कार्लसन की पोस्ट में संभावित परमाणु हमले या नेतन्याहू द्वारा डाले जा रहे कथित दबाव के दावों के समर्थन में कोई ऐसा सबूत नहीं दिया गया, जिसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जा सके।

कार्लसन का दावा है कि नेतन्याहू युद्ध जारी रखना चाहते हैं। कार्लसन ने सैन्य कार्रवाई के कथित जोर को, पिछले हफ्ते इज़राइल में हुए चुनावों के बाद नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति से जोड़ा है। उन्होंने दावा किया कि ट्रम्प के सीधे हस्तक्षेप के बिना इज़रायली प्रधानमंत्री के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा, और अगर वे सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तो उन्हें जांच का सामना करना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। कार्लसन ने लिखा कि नेतन्याहू को ट्रम्प के करीब रहना होगा। उन्हें इस युद्ध की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका के कई वरिष्ठ अधिकारी नेतन्याहू के रुख का समर्थन कर रहे हैं और ईरान के साथ बातचीत के ज़रिए किसी समझौते के ख़िलाफ़ हैं। कार्लसन ने



अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर का नाम लिया, और साथ ही दावा किया कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो और सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ भी इज़रायली प्रधानमंत्री के इशारों पर चल रहे हैं। कार्लसन ने आगे दावा किया कि हाल ही में दोहा में हुई एक बैठक के दौरान, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ शांति समझौते के मसौदे का विरोध किया था। उन्होंने इस दावे को साबित करने के लिए कोई विवरण या सबूत नहीं दिया। टिप्पणीकार ने यह भी कहा कि 27 सितंबर को नेतन्याहू चुपके से अबू धाबी गए थे, ताकि ईरान के ख़िलाफ़ अंतिम सैन्य अभियान के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का समर्थन हासिल कर सकें, लेकिन यूएई ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

क्षेत्रीय और वैश्विक परिणामों को लेकर चेतावनी

कार्लसन ने चेतावनी दी कि तनाव और बढ़ने से खाड़ी क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों को हुए नुकसान और ऊर्जा तथा उर्वरक बाजारों में आई बाधाओं की ओर इशारा किया। उन्होंने दावा किया कि अक्टूबर में होर्मुज जलडमरूमध्य में, दुनिया भर में तेल ढोने वाले लगभग 850 सुपरटैंकरों में से 11 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। संभावित परमाणु हमले के परिणामों पर, कार्लसन ने आरोप लगाया कि %पिकएक्स माउंटेन% पर ज़मीनी विस्फोट से फारस की खाड़ी प्रदूषित हो सकती है और 10 करोड़ लोगों की जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अन्य देशों के लिए एक मिसाल बन सकता है। कार्लसन ने दावा किया कि रूस ने कम से कम दो सरकारों से कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करता है, तो उसे यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की छूट मिल जाएगी। उन्होंने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से जुड़े संभावित परमाणु तनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रशासन ने फरवरी से अपने परमाणु सिद्धांत में चुपचाप बदलाव किया है, ताकि तथाकथित युद्धक्षेत्र वाले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना आसान हो सके।

टकर कार्लसन के ये दावे ऐसे समय में आए हैं जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत दोबारा शुरू कराने के लिए कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, हालांकि नए सैन्य हमलों की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को फोन पर बात की। दोनों के बीच ईरान के साथ चल रही बातचीत की स्थिति और दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने की संभावना पर चर्चा हुई।

रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू मंगलवार को होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के तुरंत बाद नए हमलों का दबाव बना रहे थे, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत को और मौका देना चाहते थे। एक इजरायली सूत्र ने इस बातचीत को कड़ा बताया, जबकि एक अमेरिकी सूत्र ने इसे सीधी और स्पष्ट बातचीत कहा। बाद में ट्रंप ने इसे बहुत अच्छी बातचीत बताया और पुष्टि की कि ईरान उन मुद्दों में शामिल था जिन पर बात हुई, हालांकि उन्होंने ज्यादा ब्योरा नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत ठीक चल रही है और उन्हें कोई बहुत जल्दी नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह संकेत भी दिया कि अमेरिका को अभी ईरान के एक-दो परमाणु ठिकानों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने खास तौर पर पिकेक्स माउंटेन का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा हम यह 10 मिनट में कर सकते हैं। हमारे पास इसकी पूरी योजना है। आप पिकेक्स माउंटेन को देख सकते हैं। हमें उससे निपटना होगा और हम इसे बहुत तेजी से कर सकते हैं।

इसी बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पिछले हफ्ते ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेज़ाई को एक पत्र भेजा, जिसमें बातचीत दोबारा शुरू करने की संभावना पर बात की गई थी। कतरी मध्यस्थों ने भी रविवार को लगातार तीसरे दिन ईरानी अधिकारियों के साथ चर्चा की, ताकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सीधी बातचीत शुरू कराने के लिए सहमति बन सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है और आगे की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि अमेरिका, तेहरान के सवालों के जवाब कैसे देता है। अराघची ने कहा हम इस दिशा में हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा पक्ष इतनी समझदारी दिखाएगा कि अन्य रास्तों के बजाय कूटनीति को चुने। दूसरी तरफ, कार्लसन का दावा है कि ट्रंप इस समय वेंस और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की सलाह सुन रहे हैं, जिनका मानना है कि ईरान के साथ अब भी समझौता संभव है। कार्लसन ने अमेरिकी प्रशासन से परमाणु तनाव के खतरे की चेतावनी देते हुए कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की।

आज का इतिहास

1639 मैसाच्युसेट्स में पहले डाकघर की स्थापना।
1678 जर्मनी की विशेष सेना ब्रैंडनबर्गर्स ने स्वीडन में ग्रीफ्सवाल्ड शहर पर कब्जा जमाया।
1725 स्पेन और आस्ट्रिया ने गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किये।
1811 स्पेन के खिलाफ मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष।
1854 क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांस की संयुक्त सेना ने इकेरमान में रूसी सेना को पराजित किया।
1872 उल्येसेस एस ग्रांट अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित।
1914 इंग्लैंड एवं फ्रांस द्वारा तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा।
1920 इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की स्थापना।
1930 अमेरिका के महान् साहित्यकार सिन्क्लेयर लेविस को उनकी कृति 'बाबित्त' के लिये साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला।
1951 नावेदा परमाणु परीक्षण केंद्र में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया।
1961 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न्यूयार्क की यात्रा की।
1976 सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया।
1985 24 वर्ष तक शासन करने के बाद तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे द्वारा पदत्याग।
1995 इस्त्रायल के प्रधानमंत्री यित्जाक रॉबिन की गोली मारकर नृशंस हत्या।
1999 वेस्टइंडीज के महानतम तेज गेंदबाज़ मैल्कम मार्शल का निधन।
2001 भारत तथा रूस ने अफ़ग़ान सरकार में तालिबान की भागीदारी नामंज़ूर की।
2002 ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी ने जेल में बंद देश के शीर्ष असंतुष्ट नेता अब्दुल्ला नूरी को आम माफी दी।
2004 गाजा पट्टी और पश्चिमी तट की चार बस्तियों को ख़ाली करने संबंधी प्रधानमंत्री एरियल शैरोन की योजना को इस्त्रायली संसद ने मंजूरी दी।
2006 इराक के उच्चाधिकार न्यायाधिकरण ने देश के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मानवता के खिलाफ़ अपराध का दोषी पाते हुए फाँसी की सज़ा सुनाई।
2007 चीन का पहला अंतरिक्ष यान चेंज-1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा।
2012 सीरिया में आत्मघाती बम विस्फोट में 50 सैनिक मरे।
2013 भारत ने अपने पहले मंगल ग्रह परिक्रमा अभियान (एमओएम) के लिए ध्रुवीय रॉकेट को 5 नवम्बर, 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके इतिहास रच दिया।

जन-महाभियोग: लोकतंत्र की चिंता या राजनीतिक दबाव की नई रणनीति?

सौरभ वार्ष्णेय

लोकतंत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्षता जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसकी संवैधानिक स्वतंत्रता और संस्थागत गरिमा को बनाए रखना भी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जन-महाभियोग जैसा अभियान चलाना कोई सामान्य राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर और असाधारण परिस्थिति का संकेत है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक असहमति को इस स्तर तक ले जाना उचित है और क्या इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास मजबूत होगा?कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन-महाभियोग प्रस्ताव कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की चुनाव आयुक्त से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि उसकी लड़ाई निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। खडगे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देश पर चुनाव आयोग काम कर रहा है तथा देश में मताधिकार की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। इन आरोपों के बीच उन्होंने विपक्ष की ओर से लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी व्यक्त किया। निश्चित रूप से चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान की निष्पक्षता पर सवाल उठना गंभीर विषय है, लेकिन इस विषय को समझने के लिए राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़कर तथ्यों और संवैधानिक मर्यादाओं का परीक्षण करना आवश्यक है।भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां चुनाव केवल सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता की राजनीतिक इच्छा और संवैधानिक अधिकारों की अभिव्यक्ति हैं। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान ने सौंपी है। इसलिए उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठना अस्वाभाविक नहीं है। विपक्ष को यह अधिकार है कि वह चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता, पक्षपात या मतदाता अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आवाज उठाए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक मंचों से लगातार आरोप लगाने और जन-महाभियोग जैसी पहल करने से समस्या का समाधान निकल सकता है?महाभियोग की अवधारणा अपने आप में अत्यंत गंभीर है। यह किसी राजनीतिक असहमति का सामान्य हथियार नहीं, बल्कि संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा विषय है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया भी संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की संवैधानिक प्रक्रिया आवश्यक होती है। ऐसे में किसी व्यक्ति के खिलाफ जन-महाभियोग का राजनीतिक अभियान चलाना और वास्तविक संवैधानिक महाभियोग की प्रक्रिया अलग-अलग बातें हैं। जनता के बीच विरोध



दर्ज कराना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसे संवैधानिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं माना जा सकता।

यह भी समझना होगा कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाना कोई सामान्य राजनीतिक घटना नहीं है। इससे देश और विदेश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। यदि चुनाव आयोग वास्तव में किसी प्रकार की अनियमितता कर रहा है तो उसके प्रमाण सार्वजनिक किए जाने चाहिए। चुनावी आंकड़ों, मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर ठोस सवाल उठाए जाने चाहिए। विपक्ष को संसद, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक मंचों का इस्तेमाल करना चाहिए। केवल राजनीतिक भाषणों और आरोपों से किसी संस्था की निष्पक्षता प्रमाणित या खारिज नहीं की जा सकती।

दूसरी ओर, सत्ता पक्ष की भी यह जिम्मेदारी है कि वह विपक्ष की हर आलोचना को राजनीतिक हताशा बताकर खारिज न करे। लोकतंत्र में विपक्ष केवल चुनाव लडने और सरकार बदलने के लिए नहीं होता, बल्कि वह सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली महत्वपूर्ण शक्ति है। यदि विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है तो सरकार और आयोग को तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए। पारदर्शिता से बचने या सवाल पूछने वालों को राजनीतिक विरोधी बताने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती है।

वास्तविक चिंता यह है कि देश की राजनीति में संवैधानिक संस्थाएं भी आरोप-प्रत्यारोप के केंद्र में आती जा रही हैं। कभी संसद की कार्यवाही पर सवाल उठते हैं, कभी न्यायपालिका की टिप्पणियों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विवाद खड़ा होता है। ऐसी परिस्थितियां किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा किसी सरकार या राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं होती। उनका सम्मान और स्वतंत्रता पूरे देश की सामूहिक जिम्मेदारी है।

खडगे की पहल को केवल राजनीतिक विरोध कहकर खारिज करना भी उचित नहीं होगा और उसे लोकतंत्र की रक्षा का अंतिम रास्ता मान लेना भी सही नहीं है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन विरोध की भी एक संवैधानिक मर्यादा होती है। किसी पदाधिकारी को हटाने की मांग करने से पहले आरोपों की प्रमाणिकता, प्रक्रिया की वैधता और उसके परिणामों पर गंभीर विचार होना चाहिए। अन्यथा संस्थाओं के प्रति अविश्वास की ऐसी राजनीति जन्म ले सकती है, जिसका नुकसान अंततः आम मतदाता को उठाना पड़ेगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को केवल बयानों से नहीं, बल्कि पारदर्शी कार्यप्रणाली और जवाबदेही से साबित करे। विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आरोपों के साथ ठोस प्रमाण प्रस्तुत करे। सरकार को चाहिए कि वह चुनावी व्यवस्था से जुड़े हर संदेह का समाधान लोकतांत्रिक संवाद के माध्यम से करे। आखिरकार चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के मताधिकार का संरक्षक है।

लोकतंत्र में किसी के खिलाफ जन महाभियोग जैसी असाधारण पहल होना अपने आप में सुखद स्थिति नहीं कही जा सकती। यह राजनीतिक व्यवस्था में गहरे अविश्वास और संवाद की कमी का संकेत है। लेकिन इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब होगी, जब चुनाव जैसी लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ जाए। इसलिए जरूरी है कि न सत्ता पक्ष अपनी शक्ति के अहंकार में संवैधानिक मर्यादाएं भूले और न विपक्ष राजनीतिक विरोध को संस्थागत टकराव का रूप दे। लोकतंत्र की असली जीत किसी व्यक्ति के इस्तीफे या किसी दल की राजनीतिक सफलता में नहीं, बल्कि निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र संस्थाओं और जनता के अटूट विश्वास में निहित है।

ट्रंप के अच्छे या बुरे दिन आने वाले हैं?

अभिनय आकाश

जनवरी 2025 में सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ चुका है उनका सबसे बड़ा सियासी इम्तिहान—अमेरिका के मिडटर्म इलेक्शंस! सवाल सिर्फ संसद में बहुमत का नहीं, बल्कि यह तय होने का है कि अगले दो साल ट्रंप वाइट हाउस से हुक्म चलाएंगे या फिर वॉशिंगटन में उनके हर फैसले पर ब्रेक लग जाएगा। राष्ट्रपति चार साल के लिए चुना जाता है, लेकिन अमेरिकी संसद हर दो साल में जनता की अदालत में खड़ी होती है। ट्रंप के चार साल के कार्यकाल के ठीक आधे रास्ते पर होने वाले इस चुनाव का असली गणित क्या है, और यह नतीजे कैसे तय करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की दिशा? ऐसे में नवंबर 2026 में होने वाले ये जो उनके चुनाव हो रहे हैं कार्यकाल के बीच में हो रहे हैं और इसलिए उसे हम मिड टर्म चुनाव कहा जा रहा है। अमेरिकी संसद के दो सदन होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को प्रतिनिधि सभा और सीनेट को उच्च सदन कहा जाता है। मिड टर्म चुनाव में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों पर मतदान होते हैं। वहीं सीनेट की कुल 100 सीटों में से इस बार 35 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसके अलावा कई राज्यों में गवर्नर के भी चुनाव किए जा रहे हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का ही होता है। इसलिए इनकी सभी सीटों पर हर 2 साल में चुनाव होता है। जबकि दूसरी तरफ जिन हम 100 सेनेटर्स की बात कर रहे थे वो सेनेटर्स का कार्यकाल छ साल का होता है। सीनेट की सभी सीटों पर एक साथ चुनाव भी नहीं होता बल्कि हर 2 साल में करीब 1/3 सीटों पर मतदान होता रहता है। सवाल का जवाब है हां। अमेरिकी राष्ट्रपति सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। कमांडर इन चीफ मिड टर्म चुनाव में हार के बाद भी ट्रंप के पास सेना का नेतृत्व करने, विदेश विदेशी देशों के साथ बातचीत करने, कई विदेश नीति संबंधी फैसले लेने का उनके पास अधिकार होगा। हालांकि पेच भी है। युद्ध की घोषणा, सैन्य खर्च, रक्षा बजट जैसे महत्वपूर्ण मामलों में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए बड़े सैन्य अभियान और लंबे समय तक चलने वाली नीतियों में जो संसद है वो वहां से उनका विरोध हो सकता है जिससे वो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अमेरिका की जो चुनाव व्यवस्था है वह इस तरह बनाई गई है कि जनता को हर 2 साल में अपने प्रतिनिधियों के कामकाज पर राय देने का मौका मिल जाए। प्रतिनिधि सभा के सदस्य केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं ताकि वह लगातार अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह बने रहे। सीनेट में स्थिरता बनाए रखने के लिए सदस्यों का कार्यकाल छ साल रखा गया और चुनाव अलग-अलग चरणों में होते हैं। इससे संसद में एक साथ बड़े बदलाव की संभावना जो है वो कम रहती है। अगर रिपब्लिकन पार्टी बहुमत बरकरार रखती है तो ट्रंप के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना आसान होगा। यानी कि जिस हौकने के अंदाज में ट्रंप अमेरिका में बातचीत करते हैं वो तेवर उनके जारी रह सकते हैं। लेकिन अगर यहां झटका लग गया तो ट्रंप के तेवर में नरमी आएगी। काम कराने के लिए कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के आगे हाथपांव जोड़ने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो प्रतिनिधि सभा या सीनेट में बहुमत हासिल कर लेती है तो ट्रंप के कई फैसले जैसे कि विधाई प्रस्ताव को रोकने उसमें बदलाव करने की उसकी ताकत बढ़ जाती है। संसद की समितियां सरकारी कामकाज की जांच कर सकती हैं और प्रशासन से जवाब मांग सकती हैं। हालांकि मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार का मतलब यह नहीं होगा कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़े। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। संसद में बहुमत गवाने से राष्ट्रपति अपने पद से नहीं हटते हैं। अमेरिका में 2026 के मध्यावधि (मिडटर्म) चुनावों के बीच एक और बेहद संवेदनशील परिदृश्य की चर्चा हो रही है—देश में नेशनल इमरजेंसी (राष्ट्रीय आपातकाल) की घोषणा।

हालिया विधान परिषद चुनाव स्थानीय मुद्दों का महत्व दर्शाते हैं

कल्याणी शंकर

चार राज्यों में हुए द्विवार्षिक विधान परिषद चुनावों ने एक बार फिर देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। इसका मुख्य निष्कर्ष यह है कि स्थानीय कारक और क्षेत्रीय विविधताएं ही परिणामों को तय करती हैं, जिससे ये चुनावी मुकाबले बदलते राजनीतिक रुख और जमीनी स्तर पर मतदाताओं के मिजाज के शुरुआती संकेत बन जाते हैं। इन मुकाबलों में कांग्रेस और भाजपा ऐतिहासिक रूप से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष करती रही हैं और क्षेत्रीय दलों के उभार ने स्थानीय कारकों के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है।

ये 28 सीटें विधानसभा क्षेत्रों से भिन्न हैं। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में विशिष्ट व्यावसायिक श्रेणियों के पंजीकृत मतदाताओं का एक सीमित निर्वाचक मंडल होता है। मतदान में मतपत्रों और वरीयता मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है, इसलिए उम्मीदवारों के व्यक्तिगत संपर्क, नैटवर्क और प्राथमिकताओं के हस्तांतरण की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इन चुनावों में पंजीकृत स्नातकों और शिक्षकों का एक छोटा निर्वाचक मंडल शामिल होता है और अक्सर स्थानीय राजनीतिक समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस इस नतीजे को नजरअंदाज नहीं कर सकती। सभी 28 निर्वाचन क्षेत्रों में, कांग्रेस को उस राज्य में अपनी सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा जहां उसकी अपनी सरकार है। कर्नाटक में विपक्ष की जीत बेहतर समन्वय के महत्व को भी दर्शाती है। भाजपा और



जद (एस) ने सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा, जिसमें भाजपा ने 3 और जद (एस) ने 1 सीट जीती।

भाजपा ने कई परिषदों में अपनी स्थिति मजबूत की, विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और उसे नागपुर से केवल 1 सीट मिली। कांग्रेस अपनी सत्ता वाले राज्य कर्नाटक में 1 भी सीट नहीं जीत सकी, जबकि भाजपा को बनारस में एक सीट गंवानी पड़ी; यह हार एक बड़ा झटका थी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी संसद में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया। दोनों पार्टियों का प्रदर्शन भारत के जटिल राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है, जिसमें क्षेत्रीय दलों ने भी उल्लेखनीय पैठ बनाई है। यह इस मुख्य विचार को और पुख्ता करता है कि स्थानीय और क्षेत्रीय कारक किसी सीधे राष्ट्रीय मुकाबले पर भारी पड़ते हैं।

कांग्रेस को भविष्य में अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत है। उसने समावेशी शासन, स्थानीय विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर प्रचार किया, जबकि पार्टी के नेताओं ने बेरोजगारी, ग्रामीण संकट और स्थानीय प्रशासन में अधिक पारदर्शिता के मुद्दों को उठाया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सी.ई.सी.) को हटाने की भी मांग की। पार्टी के भीतर की राजनीति और गलत उम्मीदवार चयन के कारण कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा। वह किसानों, अल्पसंख्यकों और युवाओं सहित अपने पारंपरिक जनाधार को एकजुट करने में भी नाकाम रही। संगठनात्मक कमजोरियों और गुटबाजी ने जनसंपर्क को प्रभावित किया और आंतरिक भीतरघात साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि विभिन्न गुट वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट थे। पार्टी जीतने योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सकी।

भाजपा ने अपने सुशासन के रिकॉर्ड, बुनियादी ढांचे के विकास और कानून-व्यवस्था में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। पार्टी के अभियान में केंद्रीय और राज्य नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी रही, जिसका उद्देश्य एकजुटता और कुशलता का संदेश देना था। उसका यह संदेश शहरी और अर्ध-शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावी रहा, जहां मतदाताओं ने आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास के वादों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इसके बावजूद, पार्टी को उन क्षेत्रों में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जहां सत्ता-विरोधी लहर प्रबल थी या जहां स्थानीय मुद्दों ने राष्ट्रीय मुद्दों को पीछे छोड़ दिया था। दोनों दलों की तुलना करने पर, कांग्रेस और भाजपा दोनों में मजबूती और कमजोरी के पहलू दिखाई देते हैं। ये परिणाम इस मुख्य विचार की पुष्टि करते हैं-इस खंडित मुकाबले में केवल विचारधारा की तुलना में प्रदर्शन, स्थानीय सरोकार और गठबंधन अधिक मायने रखते हैं। कांग्रेस की सफलताएं अक्सर प्रभावी गठबंधन निर्माण और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने से जुड़ी रहीं, जबकि भाजपा की जीत उसके मजबूत संगठनात्मक तंत्र के जरिए समर्थन जुटाने की क्षमता को दर्शाती है। मतदाताओं के रुझान बताते हैं कि वे पार्टियों को केवल विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कामकाज के आधार पर परखने के लिए तैयार हैं, और क्षेत्रीय दलों के उभार ने इस पारंपरिक द्विध्रुवीय मुकाबले को और अधिक बांट दिया है।

दोनों दलों ने ऐसे बयान जारी किए, जिनमें नतीजों को उनकी अपनी-अपनी नीतियों का समर्थन बताया गया। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र बनारस में भाजपा उम्मीदवार की हार पर जोर दिया, जबकि भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में अपने उम्मीदवार हार गई। इस बीच, भाजपा प्रवक्ताओं ने प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत होने का उल्लेख किया। विश्लेषकों का मानना है कि ये नतीजे एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी परिदृश्य की ओर इशारा करते हैं, जहां कोई भी दल पूर्ण प्रभुत्व का दावा नहीं कर सकता।

ये परिणाम आगामी राज्य और राष्ट्रीय चुनावों की रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों दलों को इस अधिक खंडित राजनीतिक माहौल के अनुसार ढलना होगा। कांग्रेस के लिए चुनौती अपनी बढ़त को आगे बढ़ाने और संगठनात्मक कमजोरियों को दूर करने की होगी। भाजपा के लिए, शहरी क्षेत्रों में अपनी गति बनाए रखते हुए क्षेत्रीय असंतोष को दूर करना महत्वपूर्ण होगा। यह बदलता घटनाक्रम इस मुख्य विचार को रेखांकित करता है कि दोनों ही पार्टियों के लिए जमीनी जुड़ाव और गठबंधन निर्माण सबसे केंद्रीय विषय बने रहेंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों को मतदाताओं की बदलती अपेक्षाओं और क्षेत्रीय वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ढालना होगा।

आजम की गिरफ्तारी: कानून का तकाजा या सियासी टकराव का नया अध्याय?

सौरभ वार्ष्णेय

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें डासना जेल में रखा जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब उनसे पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए रिमांड लेने की तैयारी कर रहा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और उसके वित्तीय प्रबंधन में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग तथा वित्तीय अनियमितताओं की आशंका है। आजम खान की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देश की राजनीति में जांच एजेंसियों की भूमिका, राजनीतिक जवाबदेही और कानून के निष्पक्ष इस्तेमाल को लेकर बहस छेड़ दी है।

लोकतंत्र में कानून का शासन सर्वोपरि होता है। किसी व्यक्ति का राजनीतिक कद कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि उसके विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं या भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं तो जांच होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों की जवाबदेही आम नागरिकों से कम नहीं, बल्कि अधिक होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप हो। किसी व्यक्ति को राजनीतिक पहचान के आधार पर न तो अपराधी माना जा सकता है और न ही राजनीतिक सहानुभूति के आधार पर आरोपों से मुक्त किया जा सकता है।

आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक चर्चित और प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। रामपुर की राजनीति से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाने वाले आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में



शामिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सांसद के रूप में उनकी राजनीतिक भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनके विरुद्ध दर्ज विभिन्न मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों ने उनके राजनीतिक जीवन को लगातार प्रभावित किया है। अब जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई ने उनके सामने एक नई कानूनी चुनौती खड़ी कर दी है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आजम खान लगभग 11 महीने जेल में रहने के बाद शनिवार को रामपुर जेल से बाहर आए थे। लेकिन उनकी रिहाई की खुशी अधिक समय तक नहीं टिक सकी और प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें दूसरे मामले में हिरासत में ले लिया। रविवार को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब ईडी उनसे जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना, उसके निर्माण में इस्तेमाल धन, फंडिंग के स्रोत और कथित मनी ट्रेल के संबंध में पूछताछ करना चाहती है। यह पूरा घटनाक्रम कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

सबसे पहला सवाल जौहर यूनिवर्सिटी के वित्तीय प्रबंधन का है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। यदि किसी संस्थान को सरकारी सहायता, निजी दान या अन्य वित्तीय स्रोतों से धन मिला है तो उसका पूरा हिसाब-किताब सार्वजनिक और कानूनी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। आखिर धन कहां से आया, किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ और उसका उपयोग किन कार्यों में किया गया? इन सवालों का जवाब दस्तावेजों और वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर सामने आना चाहिए। यदि सरकारी धन के दुरुपयोग या अवैध लेन-देन के प्रमाण मिलते हैं तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन केवल आरोपों के आधार पर किसी को दोषी ठहराना न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और उनकी कार्यप्रणाली से जुड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी दलों के अनेक नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आते रहे हैं। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है, जबकि सरकार और जांच एजेंसियां इन कार्रवाइयों को कानून के तहत की गई जांच बताती हैं। ऐसे में जनता के मन में उठने वाले संदेहों को दूर करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इसका सबसे प्रभावी तरीका यही है कि जांच एजेंसियां अपने प्रत्येक कदम को ठोस साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर उचित ठहराएं।

आजम खान के मामले में भी समाजवादी पार्टी की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन इन आरोपों की सत्यता का फैसला अदालत और उपलब्ध साक्ष्य ही करेंगे। इसी तरह ईडी के आरोपों को भी अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। जांच और मुकदमे के बीच अंतर समझना जरूरी है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी बचाव का अधिकार देता है। आजम खान को भी यह अधिकार पूरी तरह मिलना चाहिए।

इस प्रकरण का एक व्यापक पक्ष शिक्षा और सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता से भी जुड़ा है। जौहर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान केवल किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं होते, बल्कि उनसे हजारों विद्यार्थियों और कर्मचारियों का भविष्य जुड़ा होता है। यदि वित्तीय अनियमितताओं के कारण किसी विश्वविद्यालय की गतिविधियां प्रभावित होती हैं तो सबसे अधिक नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है। इसलिए जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के हित अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों।

राजनीतिक दलों को भी इस मामले में संयम बरतने की जरूरत है। सत्ता पक्ष को जांच को अपनी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने से बचना चाहिए और विपक्ष को भी हर कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में न तो जांच एजेंसियां किसी सरकार की निजी संस्था हैं और न ही राजनीतिक नेता कानून से ऊपर हैं। इसी तरह सरकार को भी यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह जांच के नाम पर किसी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करे। आजम खान का मामला केवल एक नेता की गिरफ्तारी या जेल भेजे जाने तक सीमित नहीं है। यह देश की न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता और राजनीतिक जवाबदेही की कसौटी भी है। ईडी को यदि वित्तीय अनियमितताओं के प्रमाण मिले हैं तो उन्हें अदालत के सामने मजबूती से प्रस्तुत करना चाहिए। आजम खान को भी अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का कानूनी जवाब देने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। अदालत को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय करना चाहिए।

कांग्रेस की रैली - 'खाली खाली कुर्सियां, खाली खाली तम्बू हैं' और भेजा...?

राकेश सैन

फिल्म मेरा नाम जोकर के गीत 'खाली-खाली कुर्सियां हैं खाली खाली तम्बू हैं' के गीतकार गोपालदास 'नीरज' अगर 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की रैली को देखते तो वहां की खाली कुर्सियां व खाली तम्बू देख कर वैचारिक पक्ष से लिख रहे होते कि 'खाली खाली भेजा है।' रैली में किसी भी नेता द्वारा ऐसी कोई तथ्यात्मक बात नहीं कही गई जिससे यह साबित होता हो कि वोटों की चोरी हुई है और एसआईआर में गड़बड़ी है। जो जो बातें बोली गईं, चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री व गृहमंत्री को लेकर जो जो अपशब्द बोले गए वो सब पिछले कई महीनों से गढ़े जा रहे झूठे नैरेटिव के प्रयासों से अतिरिक्त कुछ नहीं था। शायद यही कारण है कि न तो देशवासियों ने इस रैली से पहले विपक्ष को गंभीरता से लिया और न ही बाद में इन बातों पर ध्यान दे रहा है। कांग्रेस चाहे इस रैली को लेकर कितनी भी उत्साहित नजर आए परंतु यह तो सच्चाई है कि रैली में उमड़ी भीड़ दस लाख के दावे के मुकाबले कहीं अधिक कम रही। रही सही कसर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजु ने यह दावा करके पूरी कर दी है कि कांग्रेस जिन तस्वीरों से रैली की भीड़ दिखा रही है वह कृत्रिम बुद्धिमता से तैयारी की गई है। रैली के दौरान व इससे पूर्व कथित जनसंसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों को जिस तरीके से अवैध बताया इससे तो उन्होंने अपने नेता पद को भी अवैधानिक घोषित कर दिया है। दुनिया के राजनीतिक इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि संवैधानिक पद पर विराजमान किसी नेता ने अपने ही पद को अवैध घोषित किया हो। अब प्रश्न है कि अगर उनका पद ही अवैध है तो वे इस पद से अभी तक चिपके हुए क्यों हैं? वैसे तो नेता प्रतिपक्ष कई महीनों से वोट चोरी का झूठ फैला रहे हैं परंतु कांग्रेस को वोट चोरी का अपना अभियान तेज करने का मौका कुछ दिन पहले की उस खबर से मिला, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि एसआइआर के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथपत्र देकर स्पष्ट रूप से कहा कि एसआइआर पर सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से हुए। इसके बाद भी विपक्षी दल अपने इस हठ पर कायम हैं कि वोट चोरी हो रही है। वे इस तथ्य पर भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं कि जिन 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट हटाए गए हैं, वे उनके हैं जो अन्यत्र जा बसे हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है अथवा जिनके नाम दो-तीन जगह दर्ज थे। सच यह भी है कि 13 करोड़ लोगों का नाम हटाने का फैसला अंतिम नहीं है और वैध मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में अभी भी शामिल करा सकते हैं। इतना होने के बावजूद उक्त रैली की कुर्सियां व तम्बू खाली होने के साथ-साथ वैचारिक रूप से भेजा खाली होना न कहा जाए तो क्या कहें? विडंबना यह भी है कि न्यायालय में एसआइआर के खिलाफ याचिका दायर करने वाले विपक्षी नेता कथित वोट चोरी के खिलाफ कोई प्रमाण अदालत के समक्ष पेश करने के बजाय दिखावटी संसद बुलाकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जन महाभियोग पारित करने जैसे स्वांग कर अपना ही उपहास ही उड़ा रहे हैं। रैली की वैचारिकता के साथ-साथ इसमें जुटी भीड़ को लेकर जिस तरह से झूठ का सहारा लेने के आरोप लग रहे हैं वह साफ दर्शाता है कि खुद विपक्ष इस रैली से निराश है और येन केन प्रकारेन रैली को अधिक से अधिक सफल होने के दावे कर रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल ने रैली में भारी भीड़ दिखाने के लिए एआई से बनी फर्जी तस्वीरों का सहारा लिया है। किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेलंगाना से कांग्रेस सांसद वामसी गड्डम और अन्य नेताओं द्वारा साझा की गई एक तस्वीर को पोस्ट करते हुए कटाक्ष किया। रिजिजू ने लिखा कि रामलीला मैदान को खचाखच भरा दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी की फेक नैरेटिव टीम एआई से बनी नकली फोटो भी ठीक से नहीं बना पाई।



कोरोना महामारी के दौरान बच्चे अपने पाठ्यक्रम में से ऐसी विभिन्न कक्षाओं में दाखिला और भाग ले रहे हैं जो उनके कौशल को बढ़ाने के लिए उनके स्कूल द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह पैटर्न विभिन्न आयु समूहों में देखा गया है जिसके कारण भारत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मांग बढ़ रही है।

बच्चों को घर बैठे खेल-खेल में सिखाएं गणित के गुण

कोरोना वायरस महामारी के बाद कई छात्र काफी मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं। इस तनाव को दूर करने के लिए कई छात्र नए-नए हुनर सीख रहे हैं। ऐसे में भारत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मांग काफी बढ़ गई है। माता-पिता अपने बच्चों को नए कौशल सिखाने के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को गणित और सांख्यिकी गणना सिखाना चाहते हैं तो अबेकस ट्रेनिंग क्लास की मदद से आप अपने बच्चों को खेल में गणित पढ़ा सकते हैं।

कोरोना महामारी के दौरान बच्चे अपने पाठ्यक्रम में से ऐसी विभिन्न कक्षाओं में दाखिला और भाग ले रहे हैं जो उनके कौशल को बढ़ाने के लिए उनके स्कूल द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह पैटर्न विभिन्न आयु समूहों में देखा गया है जिसके कारण भारत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मांग बढ़ रही है। माता-पिता अलग-अलग ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिसके माध्यम से उनके बच्चों को रचनात्मक सीखने के माहौल में पाला जा सकता है। गणित और संख्या कुछ बच्चों के लिए स्वाभाविक रूप से आती है, लेकिन जब गणना की बात आती है तो स्कूल और कॉलेज के छात्रों का एक बड़ा हिस्सा कुछ हद तक संघर्ष करता है। अबेकस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सदियों से मौजूद है और इसे अंकगणितीय कौशल और संख्यात्मक प्रवाह को विकसित करने के लिए दुनिया भर में सबसे अच्छे उपकरणों में से एक माना जाता है। अबेकस टूल का उपयोग गणितीय कार्यों जैसे जोड़, घटाव, गुणा, वर्ग या घनमूल को करने के लिए किया जाता है। अबेकस का उपयोग दशमलव अंक, ऋणात्मक संख्या और बहुत कुछ गिनने के लिए भी किया जा सकता है। अपने गणना कौशल में सुधार के अलावा, अबेकस सीखने से बच्चे के समग्र विकास में मदद मिल सकती है। अबेकस सीखने के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

- कैलकुलेशन की गति और सटीकता में सुधार करता है
- विश्लेषणात्मक कौशल और तार्किक रीजनिंग का निर्माण करता है
- गणित में रुचि पैदा करता है
- एकाग्रता और अवलोकन शक्ति को बढ़ाता है
- मेमोरी में सुधार करता है
- आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान बनाता है



यहां भारत में पांच ऐसे प्लेटफार्मों के बारे में बताया गया है जो 100 प्रतिशत डिजिटल एबेकस प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और युवाओं को भविष्य के रोल मॉडल बनने के लिए प्रेरित करते हैं।

ब्रिटिश यूथ इंटरनेशनल कॉलेज

यूके स्थित प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन अबेकस शिक्षण मंच लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। उनके मंच में पूरी तरह कार्यात्मक वर्चुअल अबेकस है जो बच्चों के समग्र मानसिक विकास के लिए इंटरैक्टिव प्रशिक्षक के नेतृत्व वाली अबेकस शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है। ये ऑनलाइन कक्षाएं चरण-दर-चरण अप्रोच प्रदान करती हैं जिसका उद्देश्य छात्रों को अबेकस को ध्यान में रखकर मार्गदर्शन करना और कैलकुलेटर की तुलना में तेजी से संख्या की गणना करना है। शिक्षक प्रत्येक छात्र को गहन शिक्षण प्रदान करते हैं। वे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव जोड़, दशमलव घटाव, दशमलव गुणा और दशमलव भाग को कवर करते हैं। वे एकमात्र अबेकस कंपनी हैं जो दशमलव आधारित गणना प्रदान करती हैं।

उडेमी

उदमी अबेकस कोर्स का उद्देश्य आपकी गणना, क्षमता, संख्या बोध और मानसिक अंकगणित को बेहतर बनाने में मदद करके मस्तिष्क का विकास करना है। यह पाठ्यक्रम मल्टीमीडिया और एनिमेशन के जरिये आपको सिखाएगा कि अबेकस पर सही और तेज बुनियादी गणित संचालन कैसे करें। इन अबेकस ऑनलाइन कक्षाओं को शुरू करके बच्चे अबेकस पर संख्याएं रखने, हल करने और जोड़ और घटाव को समझने में सक्षम होंगे।

अबेकस सुपरमैथ्स

'सुपरमैथ्स' छात्रों को अबेकस टूल का उपयोग करने के लिए एक दोस्ताना और इंटरैक्टिव मंच प्रदान करता है। उनकी कक्षाएं आपको ऑनलाइन वर्कशीट पर काम करके मानसिक सिद्धांत अवधारणाओं को अभ्यास में लाने की अनुमति देती हैं। यह कोर्स दो ट्रैक में आता है, जूनियर और सीनियर। पहले ट्रैक में 11 स्तर होते हैं जबकि दूसरे वरिष्ठ ट्रैक में 8 स्तर होते हैं। प्रत्येक स्तर के अंत में एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाती है जिसके बाद छात्र को अगले स्तर पर पदोन्नत किया जाता है। वे प्रशिक्षक के नेतृत्व में आवेदन आधारित वीडियो कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाते हैं।

अबेकस मास्टर

अबेकस मास्टर ने अबेकस को अधिक रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए अनूठी विशेषताओं के साथ एक व्यापक शिक्षण मंच बनाया है। यह ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म 5-12 वर्ष की आयु के बीच के छात्रों को अबेकस प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें आठ स्तर शामिल होते हैं जो बुनियादी से लेकर उन्नत अबेकस गणनाओं तक सभी विषयों को कवर करते हैं। छात्र इस पाठ्यक्रम को अपनी गति के हिसाब से ले सकते हैं; हालाँकि, पोर्टल पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए प्रत्येक स्तर पर कम से कम दो महीने बिताने का सुझाव देता है। उनकी कक्षाएं एनिमेशन, अंजान वीडियो और प्रैक्टिस वर्कशीट की मदद से दी जाती हैं।

स्मार्ट किड अबेकस

स्मार्ट किड की 'अबेकस प्रेंग्राइजी' बच्चों के लिए अबेकस ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करती है। ये कक्षाएं सप्ताह में एक बार 45 मिनट के लिए आयोजित की जाती हैं। समय में कोई पाबन्दी नहीं है और छात्र कई प्रकार के पाठ्यक्रमों में से चुन सकते हैं। यह आठ स्तरीय पाठ्यक्रम है जिसमें 5 बुनियादी और 3 अग्रिम स्तर हैं। पाठ्यक्रम 4-14 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों के लिए डिजाइन किए गए हैं और ये पाठ्यक्रम कौशल के विकास के साथ-साथ संपूर्ण मस्तिष्क विकास को बढ़ावा देते हैं।

वैकल्पिक चिकित्सा में कॅरियर बनाना चाहते हैं तो चुनें मैग्नेटिक थेरेपी

एक मैग्नेटो चिकित्सक को मैग्नेटोमीटर के सही उपयोग के बारे में पता होना चाहिए, जो एक चुंबक के ध्रुवों को निर्धारित करता है। इसके अलावा आपको चुंबकीय चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों की भी सही जानकारी होनी चाहिए।

मैग्नेटिक थेरेपी, जिसे मैग्नेट थेरेपी या मैग्नो थेरेपी भी कहा जाता है, वास्तव में एक वैकल्पिक चिकित्सा उपचार है, जिसमें विभिन्न रोगों के उपचार के लिए चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बेहद सिंपल, इफेक्टिव, सुरक्षित व पूरी तरह से दर्दरहित प्राकृतिक उपचार है। चुंबकीय चिकित्सा को एक विज्ञान के साथ-साथ एक कला के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के विभिन्न अंगो, रोगों को जानने के साथ-साथ व मैग्नेट के उचित उपयोग को जानना भी उतना ही जरूरी है। विज्ञान में, चुंबकीय चिकित्सा एक्यूपंक्चर के समान है। वहीं कला में, इसमें विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों पर विभिन्न आकारों और शक्तियों के मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बेहद डिफरेंट चिकित्सा थेरेपी है। तो चलिए जानते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे बनाएं कॅरियर-

स्किल्स

एक मैग्नेटो चिकित्सक को मैग्नेटोमीटर के सही उपयोग के बारे में पता होना चाहिए, जो एक चुंबक के ध्रुवों को निर्धारित करता है। इसके अलावा आपको चुंबकीय चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों की भी सही जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें मानव शरीर व उसके महत्वपूर्ण अंगों की रचना व उसके विज्ञान के बारे में भी पता होना चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता

भारत में केवल कुछ ही संस्थान मैग्नेट थैरेपी पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं। मैग्नेट थेरेपी में सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 10, 2 है और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक होना आवश्यक है। डिप्लोमा कोर्स की अवधि 1 वर्ष की है और स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स 2 वर्ष का है। कुछ संस्थान शार्ट टर्म डिप्लोमा और मास्टर डिप्लोमा कोर्स भी करवाते हैं, जिनकी अवधि एक से तीन महीने की होती है। एक मैग्नेटिक थेरेपिस्ट प्राइवेट व पब्लिक हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल या वैकल्पिक उपचार चिकित्सा केन्द्रों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक थेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वह उपचार के लिए मैग्नेटिक ज्वैलरी, ब्रेसलेट व अन्य उत्पादों को भी बेच सकते हैं। एक मैग्नेटिक थेरेपिस्ट की आय असीमित है। उनकी आय उनके चिकित्सीय कौशल पर निर्भर करती है। सेल्फ इंपलायड मैग्नेटिक थेरेपिस्ट घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। उनका एक सेशन करीबन 20 से 30 मिनट का होता है।

प्रमुख संस्थान

- इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता
- एक्यूप्रेशर रिसर्च, टेनिंग व टीटमेंट इंस्टीट्यूट, जोधपुर
- ऑल इंडिया पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल, लुधियाना
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे
- कॉलेज ऑफ क्लिनकिल मैग्नेटोलॉजी और प्राण हीलिंग कॉलेज, त्रिशूर
- इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, बैंगलोर
- महेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, जयपुर





एक्वापॉनिक्स फार्मिंग में है बेहतर भविष्य

एक्वापोनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक्वाकल्चर जिसमें मछली पालन होता है और दूसरा हाइड्रोपोनिक जिसमें पानी पर खेती होती है। एक्वापोनिक्स में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियाँ और पौधे एक साथ उगाए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत खेती की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है।

आज के समय में एग्रीटेक स्टार्टअप बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। एक्वापोनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक्वाकल्चर जिसमें मछली पालन होता है और दूसरा हाइड्रोपोनिक जिसमें पानी पर खेती होती है। एक्वापोनिक्स में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियाँ और पौधे एक साथ उगाए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत खेती की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है जबकि इसमें पौधे दोगुनी रफ्तार से बढ़ते हैं। एक्वापॉनिक्स में एक फिश टैंक में मछली पालन किया जाता है और दूसरी तरफ पानी पर हाइड्रोपोनिक खेती का सिस्टम बनाया जाता है। फिश टैंक में मछलियां फीड खाने के बाद करीब 70 फीसदी तक मल निकालती हैं जिसमें अमोनिया होता है। इसके बाद फिश टैंक से अमोनिया वाले पानी को हाइड्रोपोनिक खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है तो वहां मौजूद बैक्टीरिया इसे नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं। यह पौधों के विकास के लिए बहुत ही अहम होता है। इसके बाद पानी को फिर से प्यूरिफाई किया जाता है और दोबारा मछलियों के टैंक में डाला जाता है। इस तरह एक ही पानी बार-बार इस्तेमाल होता रहता है और पानी की बचत होती है।

एक्वापोनिक फार्मिंग सेटअप तैयार करने में कितनी लागत आएगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बड़ा सेटअप तैयार करना चाहते हैं या छोटा। उदाहरण के लिए अगर आप एक एकड़ जमीन पर एक्वापोनिक फार्मिंग करते हैं तो आपका करीब 3 करोड़ रूपए तक का खर्चा आ सकता है। इसके साथ ही अगर आप मुनाफा चाहते हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी वाली चीजें इस्तेमाल करनी होंगी। एक्वापोनिक खेती से हुई पैदावार पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है इसलिए आप इसके लिए सामान्य की तुलना में दो से तीन गुना कीमत कमा सकते हैं। हालाँकि, आपको पैदावार से पहले ही उसे बेचने की तैयारी कर लेनी होगी वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप बड़े-बड़े रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट और फाइव स्टार होटलों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं।



फ्लाइट में यात्रियों की मेहमान नवाजी कर कमाएं हजारों

केबिन क्रू की जिम्मेदारी फ्लाइट में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना और यात्रियों को फ्लाइट के नियम समझाना होता है। बहुत से लोग केबिन क्रू बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि केबिन क्रू कैसे बनें।

केबिन क्रू का मतलब होता है केबिन के कर्मचारी। किसी भी फ्लाइट में जहाँ यात्री बैठते हैं, उसे केबिन कहते हैं। फ्लाइट में यात्रियों की सेवा और सुरक्षा के लिए जो टीम होती है, उसे केबिन क्रू कहते हैं। केबिन क्रू की जिम्मेदारी फ्लाइट में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना और यात्रियों को फ्लाइट के नियम समझाना होता है। बहुत से लोग केबिन क्रू बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि केबिन क्रू कैसे बनें। आज के इस लेख में हम आपको केबिन क्रू बनने के लिए जरूरी योग्यता, प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देंगे

योग्यता

- उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम में पास होना चाहिए। या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक की हो तो आप केबिन क्रू की जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक की ऊंचाई 157 से 170 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 17 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

जरूरी कौशल

- केबिन क्रू बनने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए।
- केबिन क्रू बनने के लिए दूसरों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने का ढंग होना चाहिए।
- आपके शरीर पर किसी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए।
- आपकी अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
- केबिन क्रू बनने के लिए अच्छी पर्सनालिटी और गुड लुक्स भी जरुरी होते हैं।

कोर्सेज

- डिप्लोमा इन केबिन क्रू एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट
- डिप्लोमा इन एयरलाइन एंड ट्रेवल मैनेजमेंट
- डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट
- डिप्लोमा इन एयरलाइन केबिन क्रू
- सर्टिफिकेट कोर्स इन एयर हॉस्टेस

केबिन क्रू कैसे बनें

- एयरलाइन कंपनियां समय-समय पर केबिन क्रू की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करती हैं।
- केबिन क्रू का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आवेदक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
- इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आवेदक की शारीरिक जाँच और मेडिकल टेस्ट होता है।
- मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है।
- इन सभी टेस्ट्स को पास करने वाले उम्मीदवारों का चयन केबिन क्रू के लिए होता है।

सैलरी

शुरुआत में बतौर केबिन क्रू आपकी सैलरी प्रतिमाह 30,000 रूपये से 50,000 रूपये तक हो सकती है। हालंकि, समय के साथ अनुभव होने पर सैलरी बढ़कर 70 हजार रूपये से 1 लाख रूपये प्रतिमाह तक हो सकती है।



राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राहुल की बहस की चुनौती पर सीएम हिमंत का पलटवार

गुवाहाटी। राहुल गांधी के ट्वीट पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि क्या उन्होंने पता है कि वे विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने कहा कि चर्चा करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। आप बहस की शुरुआत करें, प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे। हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा, राहुल जी, कल आपने एक वीडियो पोस्ट किया। आपने हाथ में गुलाब का फूल लिया हुआ था और प्रधानमंत्री को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे थे। राहुल जी, गुलाब तो वैलेंटाइन डे पर दिए जाते हैं, दिवाली पर नहीं। मुझे एक बात बताइए। क्या आपको पता भी है कि आप विपक्ष के नेता हैं? अगर आप विपक्ष के नेता हैं और अगर आप सच में खुद को ऐसा मानते हैं तो प्रधानमंत्री के साथ यह बहस कहां होनी चाहिए? सड़कों पर? किसी गली-कूचे में? या फिर संसद में? संसद में स्पीकर हैं, आपकी मां हैं, आपकी बहन हैं, तो फिर संसद में ही यह बहस आसानी से हो सकती है।

कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक में विश्वसनीयता की कमी : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) पर तीखा हमला बोलते हुए बुधवार को कहा कि इनके नेताओं में स्पष्टता, क्षमता और विश्वसनीयता का पूरी तरह अभाव है। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''चुनावों में हार के नए रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस और 'इंडी गठबंधन' की हताशा अब अराजकता की राजनीति में बदल गई है। इनके नेतृत्वकर्ताओं में 'क्लैरिटी, कैपेसिटी और क्रेडिबिलिटी' का पूरा अभाव है। जनादेश का अनादर इसी सोच का परिणाम है।'' उन्होंने कहा, ''इस अराजकता के विरुद्ध जनजागरण और लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा का संकल्प लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ गोरखपुर में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में सहभागिता करूंगा।'' योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

ओपी राजभर के लिए सपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है

नयी दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य राजीव राय ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के लिए सपा के साथ गठबंधन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और उन्हें दोबारा साथ लेने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सवाल किया कि राजभर के खुद को 'सबसे बड़ा गुंडा' बताने के बावजूद वह उनकी सरकार में मंत्री कैसे बने हुए हैं। राय ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा कि फिलहाल सपा की किसी अन्य छोटे दल के साथ भी गठबंधन को लेकर बातचीत नहीं हो रही है। राजभर के भविष्य में फिर से सपा के साथ आने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''राजभर से गठबंधन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिलहाल अन्य छोटे दल से भी कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही है।'' उनका कहना है कि राजभर के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं।

रैली में गैरहाजिर यूथ कांग्रेस के 202 पदाधिकारी निलंबित

नईदिल्ली। भारतीय युवा कांग्रेस ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की 'वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली' में शामिल नहीं होने पर सात राज्यों के अपने 200 से अधिक पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, संगठन की ओर से गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। गुजरात में 49, पश्चिम बंगाल में 26, उत्तर प्रदेश (मध्य) में 11, तेलंगाना में 14, हरियाणा में 10, मध्य प्रदेश में 60 और झारखंड में 32 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। इस तरह कुल 202 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। निलंबित किए गए पदाधिकारियों में प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव स्तर के नेता शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि इन पदाधिकारियों ने रैली को लेकर दिखाई गई उदासीनता के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

चुनाव आयोग ने फार्म 6 और घोषणा पत्र को ऑनलाइन किया अलग

नयी दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे के अनुरूप, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया वाले राज्यों में नए मतदाता के पंजीकरण से जुड़े फॉर्म और उसके साथ संलग्न घोषणा पत्र को ऑनलाइन प्रक्रिया में अलग-अलग कर दिया है। आयोग ने सितंबर में उन राज्यों में अपने डिजिटल मंच से घोषणा पत्र को पहले ही हटा दिया था, जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा हो चुका है। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के इच्छुक लोगों को फॉर्म-6 भरना होता है। बिहार में एसआईआर के बाद निर्वाचन आयोग ने इसके साथ एक घोषणा पत्र भी जोड़ दिया था, जिसमें फॉर्म-6 भरने वाले आवेदकों से उनके माता-पिता के एसआईआर संबंधी विवरण मांगे गए थे। हालांकि, ऑफलाइन प्रक्रिया में दोनों दस्तावेज अलग-अलग भरने होते हैं, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था में दोनों के लिए एक ही ओटीपी का इस्तेमाल किए जाने से यह सवाल उठने लगा था कि क्या आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय की मंजूरी के बिना फॉर्म-6 में बदलाव किया है।

राहुल गांधी को वित्तमंत्री सीतारमण की दो-टूक

संसद में आइए, एसआईआर और ईवीएम पर हो जाए आर-पार की बहस

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एसआईआर और ईवीएम के मुद्दे पर संसद में खुली बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर बयानबाजी और चुनौती देने के बजाय संसद में आकर अपनी बात रखनी चाहिए। सीतारमण ने यह भी याद दिलाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही इन मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कह चुके हैं।

निर्मला सीतारमण ने मंगलवार देर रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस के लिए जगह चुनने की चुनौती दे रहे हैं, जबकि बहस के लिए संसद से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? राहुल गांधी खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में उन्हें सोशल मीडिया पर चुनौती देने के बजाय सदन में चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि अमित शाह ने एक दिन पहले ही एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और ईवीएम पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की पेशकश की थी। अगर राहुल गांधी बहस को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें अपने तथ्य और सबूत लेकर सदन में आना चाहिए। साथ ही दूसरों की बात भी धैर्य से सुननी चाहिए।

सीतारमण ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब भी सरकार उनके लगाए आरोपों का जवाब देने लगती है, तब वे सदन से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब राहुल गांधी दूसरे पक्ष की बात सुनने के लिए सदन में रुकते ही नहीं हैं, तो फिर बहस की इच्छा जताने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ-साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दल भी कई बार संसद की कार्यवाही में बाधा डालते हैं। इसके चलते कई बार पूरे दिन की कार्यवाही बिना किसी कामकाज के खत्म हो जाती है। अगर विपक्ष सच में मुद्दों पर चर्चा चाहता है तो उसे पहले संसद को ठीक से चलने देना चाहिए।

वित्त मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हाल ही में आयोजित मॉक पार्लियामेंट को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस कार्यक्रम को मॉक पार्लियामेंट बताया, वह असल में संसद का मजाक उड़ाने जैसा था। सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को इस कार्यक्रम के लिए समय और उत्साह मिल गया, लेकिन असली संसद में चर्चा करने के लिए भी उन्हें उतनी ही दिलचस्पी दिखानी चाहिए। उनके मुताबिक, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करने वालों को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान अपने व्यवहार में भी दिखाना चाहिए।

सीतारमण ने राहुल गांधी से कहा कि अगर उन्हें सरकार या किसी संस्था से जुड़ी कोई शिकायत है तो वे साफ-साफ आरोप लगाएं और उसके समर्थन में सबूत भी पेश करें। उन्होंने कहा कि बिना ठोस प्रमाण के एक के बाद एक आरोप लगाने से किसी की बात मजबूत नहीं होती। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति से गंभीरता और जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। ऐसे में राहुल गांधी को अपनी बात तथ्यों के साथ रखनी चाहिए।

इस राजनीतिक बयानबाजी में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हो गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी पर तंज कसा। गोयल ने लिखा, राहुल गांधी जी, 2014 से खुद से ही बहस कर रहे हैं! आप वाकई अपनी अलग ही श्रेणी में हैं।

राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर खड़गे का पीएम मोदी पर हमला

■ **बोले- वोट चोरी के आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रहे?**

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के आरोपों पर जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री बार-बार %दिमागी नक्सल% जैसे बयान दे रहे हैं। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती दी है, लेकिन वह इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर पांच बार अपना रुख बदला है। इसमें फॉर्म-6 भी शामिल है, जिसे कथित तौर पर चुनाव आयोग के कुछ अन्य आयुक्तों ने गैरकानूनी बताया था।



मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह का दावा है कि देश में 3 करोड़ घुसपैठिए हैं। खड़गे ने सवाल किया कि इतने साल तक गृह मंत्री रहने के बावजूद वह अवैध रूप से भारत में लोगों के आने को क्यों नहीं रोक पाए। उन्होंने गृह मंत्री की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की मांग और दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई बड़ी वोट बचाओ रैली से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह परेशान हैं। उन्होंने संसद सत्र को लेकर भी सवाल उठाए। खड़गे के मुताबिक, संसद का पिछला सत्र खत्म हुए 83 दिन हो चुके हैं और अब सरकार विशेष सत्र बुलाने की बात कर रही है। खड़गे ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वह संसद में आएं, पत्रकारों के सामने खुलकर सवालों का जवाब दें और राहुल गांधी के साथ बहस करें। उन्होंने पूछा कि आखिर वोट चोरी क्यों की गई?

दरअसल, राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी ताकतों से संबंधों के आरोपों पर खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री को उनकी चुनौती दिए हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी जगह और मंच चुन सकते हैं। इस बहस में मीडिया और देश के युवा भी मौजूद रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि बहस का मुद्दा यह होगा कि देश विरोधी कौन है और विदेशी ताकतों से किसके संबंध हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस बहस के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को जज बनाया जा सकता है।

शरद पवार की दो दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिली, पीएम मोदी ने पूछा हाल

■ **कहा- 'हमें मार्गदर्शन करते रहें'**

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फोन पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर मार्गदर्शन जारी रखने का आग्रह किया। दो दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आई। पीएम मोदी ने कहा कि देश की चिंता छोड़ी जाए, वे और सुप्रिया सुले देश संभाल लेंगे।

शरद पवार की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर उनका हाल जाना और मार्गदर्शन जारी रखने का आग्रह किया।

एनसीसी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक से दो दिनों के बाद छुट्टी मिल गई है। अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ है। डॉक्टरों ने मेडिकल जांच और निगरानी के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति दी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वे मुंबई स्थित अपने आवास के लिए रवाना हो गए।



शरद पवार के करीबी विठ्ठल मणियार ने मीडिया को जानकारी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज (बुधवार, 4 नवंबर) सुबह फोन कर के शरद पवार की सेहत के बारे में पूछा। पीएम मोदी ने शरद पवार से कहा, आप अपना ख्याल रखें, हम देश का ख्याल रखेंगे। आप हमें गाइड करते रहें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सोमवार को पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि खांसी आने के बाद 85 वर्षीय नेता को रूबी हॉल क्लीनिक लाया गया।

पंजाब सीएम पर राहुल गांधी ने लगाया गंभीर आरोप

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य को दिल्ली से चलाया जा रहा है और सरकार नशीले पदार्थों की समस्या (ड्रग्स की समस्या) को रोकने में नाकाम रही है। संगरूर में कांग्रेस की इंसाफ रैली को संबोधित करते हुए, गांधी ने चिट्टा (मिलावटी हेरोइन) को पंजाब की एक बड़ी समस्या बताया।

उन्होंने कहा कि कई साल पहले मैंने कहा था कि पंजाब में नशीले पदार्थों का प्रसार हो रहा है। उस समय बीजेपी और अकाली दल ने यह कहकर बात को टाल दिया था कि राहुल गांधी को पंजाब के बारे में कुछ नहीं पता है। गांधी ने कहा लोगों को एक ऐसी सरकार चाहिए जो पंजाब के लिए काम करे। न कि आप जैसी सरकार, जो दिल्ली से चलाई जाती है।

रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह और वरिष्ठ नेता प्रताप बाजवा, विजय इंदर सिंगला, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजिंदर कौर भट्टल और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी मौजूद थे। गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आरोप पर खुली बहस की चुनौती दी कि कांग्रेस राष्ट्र-विरोधी है। उन्होंने मोदी से कहा कि वे किसी भी मंच पर आकर उनका सामना करें।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 5 विकेट से हराया

ऑकलैंड। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में डकवर्थ-लुईस (डीएलएस) नियम के तहत 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए मुकाबले में बारिश ने खलल डाला, जिसके बाद भारत को 40 ओवर में 167 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। भारतीय बल्लेबाजों ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया।



186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा। अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा काइल जैमीसन की गेंद पर खराब शॉट खेलकर बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभाली और दूसरे विकेट के लिए अहम साझेदारी कर भारतीय पारी को मजबूती दी।

ऑकलैंड में लगातार बारिश के चलते भारतीय पारी के 10.5 ओवर के बाद खेल रोकना पड़ा। मैदान पर बारिश जारी रहने के कारण मुकाबला करीब एक घंटे तक बाधित रहा। मौसम में सुधार होने के बाद खिलाड़ी दोबारा मैदान पर लौटे और मुकाबला शुरू हुआ। बारिश के कारण मैच से 10 ओवर कम कर दिए गए और भारत को 40 ओवर में 167 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला।

डकवर्थ-लुईस नियम लागू होने के बाद भारतीय टीम को जीत के लिए 40 ओवर में 167 रन बनाने थे। खेल दोबारा शुरू होने के समय भारत का स्कोर 10.5 ओवर में एक विकेट पर 54 रन था। 11 ओवर पूरे होने तक टीम ने 55/1 रन बना लिए थे। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के सामने मुकाबला जीतने का अच्छा मौका था। इससे पहले भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। उन्होंने अपने 10 ओवर के स्पेल में 70 रन देकर चार विकेट हासिल किए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 383 अंक उछला निफ्टी 23960 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों में धनतेरस और दीवाली से पहले खरीदारी का जोश देखने को मिल रहा। बेंचमार्क इंडेक्स बुधवार को लगातार 5वें सेशन में बढ़त के साथ बंद हुए। नतीजनत, बाजार में आईटी छोड़ सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, जिसमें मीडिया इंडेक्स 5%, मेटल और रियल्टी इंडेक्स 2-2 फीसदी की बढ़ के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 383 अंकों की मजबूती के साथ 77301 पर बंद हुआ, जो सेशन के दौरान 76604 तक फिसला था। निफ्टी भी दिन के सबसे निचले स्तर 23696 से रिकवर होकर 23960 पर बंद हुआ है। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.5 फीसदी से 2 फीसदी तक की मजबूती देखने को मिली। निफ्टी में शामिल 50 में से 36 शेयर हरे निशान में बंद हुए, जिसमें भेल, अदाणी एंटरप्राइसेज और टाइटन के शेयरों में 4-4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली।

दिवाली से पहले अमूल ने दिया ग्राहकों को झटका

नई दिल्ली। दिवाली से पहले महंगाई ने आम लोगों की जेब पर एक और असर डाला है। देश की प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल ने घी और बटर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी के इस फैसले से त्योहारों के लिए मिठाइयां, पकवान और अन्य खाद्य सामग्री तैयार करने वाले परिवारों का बजट प्रभावित हो सकता है। खास बात यह है कि कीमतें बढ़ने के साथ गुजरात के कई शहरों में अमूल के गाय के घी की कमी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। अमूल ने अलग-अलग पैक की कीमतों में इजाफा किया है। नई दरों के मुताबिक, 1 किलो घी का कार्टन अब 680 रुपए में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 630 रुपए थी यानी सीधे 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 500 ग्राम प्योर घी के पाउच की कीमत 325 रुपए से बढ़ाकर 345 रुपए कर दी गई है।

सेवा क्षेत्र की गतिविधियां चार महीने के उच्चतम स्तर पर

नई दिल्ली। देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में अक्टूबर में चार महीने की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। मांग में मजबूती से कारोबारी गतिविधियों और नए ऑर्डर में बढ़ोतरी हुई, जबकि लागत का दबाव कम हुआ। बुधवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई। कंपनियां भविष्य की संभावनाओं को लेकर सतर्कता के साथ आशावादी रहीं और उन्होंने चार महीने में सबसे कम संख्या में कर्मचारियों की भर्ती की। अंतरराष्ट्रीय बिक्री में ताजा विस्तार लगभग चार साल में सबसे कमजोर रहा। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक सितंबर के 55.2 से बढ़कर अक्टूबर में 55.8 हो गया। यह चार महीने में वृद्धि की सबसे तेज रफ्तार को दर्शाता है। क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर का अंक विस्तार, जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन दर्शाता है।

नवंबर में फिर बढ़ सकते हैं सीमेंट के दाम

नईदिल्ली। देशभर में घर बनाने और निर्माण से जुड़े दूसरे कामों की लागत बढ़ सकती है। क्योंकि अक्टूबर 2026 के दौरान सीमेंट कंपनियों ने कीमतों में 15 से 20 रुपये प्रति बोरी तक की बढ़ोतरी की है। बारिश का मौसम खत्म होने और त्योहारों से पहले निर्माण गतिविधियां बढ़ने से सीमेंट की मांग में सुधार देखने को मिला है। हालांकि, नवंबर में त्योहारों के चलते मांग की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में देश के ज्यादातर हिस्सों में सीमेंट की मांग ठीक रही। मांग में सुधार का फायदा उठाते हुए कंपनियों ने कीमतें बढ़ाईं। आने वाले दिनों में हैदराबाद में सीमेंट की कीमतों में 20 से 25 रुपये प्रति बोरी की अतिरिक्त बढ़ोतरी होने की संभावना है।

अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

सच्चिदानंद शुक्ल

दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भारत की हिस्सेदारी फिलहाल लगभग 3 फीसदी तक सिमटी है मगर यहां दुनिया की 20 फीसदी आबादी रहती है। इन आंकड़ों में एक कड़वा सच छिपा है। वह कड़वा सच यह है कि भारत की आर्थिक वृद्धि का अगला चरण केवल घरेलू बाजार के भरोसे नहीं टिका रह सकता। भारत को विदेश में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ऐसे कारोबार खड़े करने होंगे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमा सकें।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित दूसरे देशों पर लगाए शुल्क परेशानी का सबब माने जा रहे हैं। मगर शुल्कों के मोर्चे पर ट्रंप का आक्रामक तेवर वास्तव में भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है। भारतीय उद्योग जगत अब शिकायतों में उलझने के बजाय मजबूती से आगे बढ़ने का रास्ता अख्तियार कर रहा है।

निर्यातक अब व्यापारिक बाधाओं को एक अभेद्य दीवार नहीं मान रहे बल्कि इन्हें एक ऐसी परिस्थिति के तौर पर देख रहे हैं जो संरचनात्मक सुधारों की जरूरत बता रही है। शुल्कों की चोट के बीच व्यापार के इस कठिन दौर से गुजरने के कारण भारत अब सस्ते उत्पादों के बड़े पैमाने पर निर्यात से आगे बढ़कर जटिल विनिर्माण, बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता, अनुसंधान एवं विकास (आरऐंडडी) और अपने ब्रांड तैयार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।

पेट्रोलियम परिशोधन (रिफाइनिंग) क्षेत्र इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देश में इस क्षेत्र की ताकत इतनी बढ़ी है कि हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को 'रिफाइनिंग महाशक्ति' की संज्ञा दी। सालाना लगभग 25.8 करोड़ टन क्षमता और स्थापित क्षमता से भी अधिक उत्पादन करने की काबिलियत के साथ भारत कच्चा तेल



आयात करता है, जटिल परिशोधन प्रक्रियाओं के जरिये उसमें मूल्यवर्द्धन करता है और फिर डीजल, पेट्रोल, विमान ईंधन और नेफ्था जैसे उत्पाद यूरोपीय संघ (ईयू) और रूस जैसे बाजारों में निर्यात करता है। घरेलू मांग पूरी करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी आपूर्ति करने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है, विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ी है और भू-राजनीतिक उथल-पुथल झेलने की भारत की क्षमता में भी इजाफा हुआ है।

दवा क्षेत्र भी शुल्कों के निशाने पर है। अमेरिका का प्रस्तावित ढांचा (जिसमें आयातित जेनेरिक दवाओं पर चरणबद्ध रूप में 100 फीसदी से 200 फीसदी तक शुल्क लगाने की बात है) इस उद्योग के आर्थिक आधार पर सीधा प्रहार करता है। देश का दवा उद्योग अपनी जेनेरिक दवाओं का 41 फीसदी हिस्सा अमेरिकी बाजार में खपाता है। इसके बावजूद, भारतीय दवा कंपनियां दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा बाजार को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। भारतीय कंपनियों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे केवल सामान्य जेनेरिक दवाओं के बजाय उच्च मूल्य वाले नवाचार की ओर बढ़ें।

सन फार्मा द्वारा ऑर्गेनन का 11.8 अरब डॉलर में अधिग्रहण इसका एक उदाहरण है। फ्लोरिडा में स्थानीय विनिर्माण और आरऐंडी को बढ़ावा देने के लिए ल्यूपिन का 25 करोड़ डॉलर का निवेश भी इसका मजबूत उदाहरण है। 'सलेक्टयूएसए' शिखर सम्मेलन में भारतीय कारोबारी दिग्गजों द्वारा अमेरिका में लगभग 20.5 अरब डॉलर निवेश का वादा किया गया था जिनमें 19 अरब डॉलर का निवेश फार्मा क्षेत्र से आया है।

स्वच्छ ऊर्जा के मामले में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। जब अमेरिका ने भारत से आयातित सोलर सेल पर 126 फीसदी की शुरुआती काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई तो भारतीय कंपनियों ने अपनी उत्पादन क्षमता कम नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने निर्यात का रुख यूरोप और पश्चिम एशिया की ओर मोड़ दिया। साथ ही, उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लाभ उठाते हुए उन्होंने अधिक कुशल मॉड्यूल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया।

वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में निर्यात का प्रदर्शन इस व्यापक रुझान की पुष्टि करता है। वस्तुओं का निर्यात सालाना आधार पर 18 फीसदी बढ़कर 260 अरब डॉलर हो गया जो वर्ष 2023 के बाद से सबसे तेज वृद्धि में एक है। वहीं, वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल निर्यात 14 फीसदी बढ़कर 476 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

सड़क सुरक्षा की दिशा में जशपुर पुलिस की अभिनव पहल, हेलमेट बैंक में उपलब्ध कराए गए 1000 हेलमेट

मुख्यमंत्री ने जशपुर में किया हेलमेट बैंक का शुभारंभ

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर पुलिस लाइन में जशपुर पुलिस द्वारा स्थापित हेलमेट बैंक का शुभारंभ किया। सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकने और नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस अभिनव पहल के अंतर्गत हेलमेट बैंक में 1000 हेलमेट उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोपहिया वाहन चालकों को यहां से अस्थायी रूप से हेलमेट उपलब्ध कराया जाएगा।



मुख्यमंत्री श्री साय ने जशपुर पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट और चारपहिया वाहन में यात्रा करते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हेलमेट का नियमित उपयोग ऐसी दुर्घटनाओं में गंभीर चोट और मृत्यु के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी सावधानी न केवल हमारा जीवन सुरक्षित रख सकती है, बल्कि हमारे परिवार को भी अपूरणीय क्षति से बचा सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को सड़क सुरक्षा को अपनी दैनिक आदत का हिस्सा बनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जशपुर पुलिस का हेलमेट बैंक एक सराहनीय और जनहितकारी नवाचार है। इस पहल के माध्यम से नागरिकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को व्यावहारिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित यातायात की संस्कृति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर प्रवास के दौरान विश्राम गृह परिसर में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की चार मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों में रहने वाले नागरिकों को उनके नजदीकी हाट-बाजारों में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल विशेष रूप से उन क्षेत्रों के नागरिकों के लिए लाभकारी होगी, जहां स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विशेष रूप से जनजातीय बहुल और दूरस्थ अंचलों में रहने वाले नागरिकों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में किसी भी व्यक्ति को उपचार से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जशपुर जैसे भौगोलिक रूप से विस्तृत और वनांचल क्षेत्रों वाले जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बनेंगी। हाट-बाजार ग्रामीण जीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने से ग्रामीणों को अपने दैनिक कार्यों के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।



स्वास्थ्य मंत्री ने पीएचसी क्षीरपानी के लिए दी 25 लाख रुपये की स्वीकृति



कवर्धा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम क्षीरपानी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम क्षीरपानी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री उन्नयन कोष से 25 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत राशि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षीरपानी में बाउंड्रीवॉल निर्माण एवं आवश्यक मरम्मत कार्य कराए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य केंद्र की आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा तथा परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर एवं सुलभ उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक अधोसंरचना और सुविधाओं का विकास होने से ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी तथा उन्हें उपचार के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता कम होगी।

महादेव एप का तार पीएमओ तक सीबीआई पीएमओ की जांच करेगी : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि महादेव सट्टा एप मामले में एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को प्रत्यार्पित करके भारत फिर रायपुर लाया गया है। इस मामले में अभी तक सिर्फ सौरभ चंद्राकर को ही रायपुर लाया गया है। जबकि सौरभ के पार्टनर रवि उप्पल और शुभम सोनी अभी भी पकड़ से बाहर है, उन्हें कब पकड़ा जायेगा? शुभम सोनी ने विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान एक वीडियो में यह दावा किया था कि महादेव सट्टा एप का वह मालिक है तथा सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल उसके लिए काम करते है। शुभम



सोनी के इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करके जारी किया था। मतलब भाजपा भी शुभम सोनी के दावे से सहमत थी। शुभम सोनी के इसी दावे के आधार पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप भी लगाया था। कांग्रेस का सवाल है शुभम सोनी को कब पकड़कर लाया जायेगा? उसके झूठे दावे के आधार पर पूरे विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर राजनैतिक लाभ लिया था।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि महादेव सट्टा एप के सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाया जाना संभव हो सका तो उसके पीछे कांग्रेस की भूपेश सरकार के ठोस प्रयास है। महादेव सट्टा एप के खिलाफ पहली एफआईआर से लेकर 72 एफआईआर तक दर्ज करने की ठोस कार्यवाहियां कांग्रेस की सरकार ने किया था। 500 से अधिक जप्तियां और गिरफ्तारियां भी कांग्रेस की सरकार ने ही किया था। सौरभ चंद्राकर को तो लाया गया है लेकिन रवि उप्पल, शुभम सोनी को कब लाया जायेगा? महादेव सट्टा एप को गूगल प्ले पर से कांग्रेस की भूपेश सरकार के अनुरोध पर ही हटाया गया था। कांग्रेस की सरकार के समय ही रायपुर पुलिस की अर्जी पर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था।

कार्यालय से फील्ड तक दिखे सक्रियता: अरुण साव

उप मुख्यमंत्री ने 'निर्माण मंथन' में प्रदेशभर के अभियंताओं को किया संबोधित



रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव आज विभागीय अभियंताओं के लिए आयोजित 'निर्माण मंथन' में शामिल हुए। लोक निर्माण विभाग की इस एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और उप अभियंताओं को सड़क, पुल एवं भवन निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, सर्वेक्षण, प्राक्कलन, निविदा प्रक्रिया और सड़कों के रखरखाव से जुड़े तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर के विशेषज्ञों और वरिष्ठ अभियंताओं के साथ लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने गुणवत्ता, तकनीक और नवाचार पर विचार-विमर्श किया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रदेशभर के अभियंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के शिल्पकार हैं। इस भूमिका और दायित्व का गंभीरता एवं सक्रियता से निर्वहन कर अधोसंरचना को मजबूत करना है। लोक निर्माण विभाग राज्य के विकास का 'ग्रोथ-इंजन' है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के बाद से पिछले 26 वर्षों में छत्तीसगढ़ में जो बड़ा परिवर्तन आया है, उसमें विभाग की बड़ी भूमिका है। लोक निर्माण विभाग ने राज्य के विकास का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अब विकास कार्यों के लिए कोई प्रतिकूलता नहीं है। पूरे प्रदेश में इसके लिए अच्छा माहौल है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अभियंताओं से कहा कि आप लोग अपनी क्षमता, दक्षता और काबिलियत से राज्य के विकास में महती भूमिका निभाएं। बदलते समय के अनुसार नई तकनीकों और मशीनरी के साथ नई कार्य प्रद्धति अपनाएं। खुद को अपडेट और अपग्रेड करें। उन्होंने कहा कि विभाग के कार्यों से हम सबकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। खराब या त्रुटिपूर्ण काम से पूरे विभाग पर प्रश्नचिन्ह उठता है। बने-बनाए पैटर्न पर चलने के बजाय आप लोग अपने विवेक और मौलिकता के साथ श्रेष्ठ काम करें। श्री साव ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानकों एवं मापदंडों का गंभीरता से पालन करें। कार्यालय से लेकर फील्ड तक सक्रिय रहकर अपना उत्कृष्ट योगदान दें। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने कार्यशाला में कहा कि निर्माण कार्यों को सकारात्मक सोच और टीम-वर्क के साथ आगे बढ़ाएं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

पानी का सदुपयोग करने के लिए यात्रियों को किया गया प्रेरित

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे द्वारा 1 से 7 नवम्बर तक आयोजित ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल में मिशन लाइफ के तहत सप्ताह के दौरान विभिन्न जागरूकता एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जल बचाएं थीम के अंतर्गत बिलासपुर मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत रेलवे कर्मचारियों, सफाई मित्रों एवं यात्रियों को जल की अनावश्यक खपत रोकने तथा जल का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने के लिए प्रेरित गया। मंडल के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वाणिज्य विभाग व चिकित्सा विभाग के पर्यवेक्षकों द्वारा कर्मचारियों तथा सफाई मित्रों को संयुक्त रूप से जल संरक्षण एवं जल के सदुपयोग की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों के आसपास एवं परिसर में स्थित वाटर बूथ, ट्यूबवेल तथा अन्य जल स्रोतों का निरीक्षण किया गया।



10 संरक्षा प्रहरियों को संरक्षा पुरस्कार से किया सम्मानित



बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल में संरक्षित रेल परिचालन के प्रति सतर्कता, सजगता एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए संभावित दुर्घटनाओं को टालने वाले मंडल के 10 रेलकर्मियों को मंडल रेल प्रबंधक श्री राकेश रंजन द्वारा संरक्षा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मानित रेलकर्मियों में राकेश कुमार चौरसिया (सहायक लोको पायलट), पी.एस. राव (ट्रेन मैनेजर),प्रफुल्ल रंजन कुमार (जेई/पी.वे),अरुण कुमार (वरिष्ठ ट्रेन मैनेजर), श्रीमती प्रेमलता (सहायक/सी एंड डब्ल्यू),दिलीप कुमार बर्मन (स्टेशन मास्टर),अनुराग कुमार गुप्ता (टीएम-आईवी/डीटीएम-11), जयराम कुमार (सहायक लोको पायलट),एस.के. पाठक (गेटमैन बीके-69) एवं विनोद कुमार (वरिष्ठ ट्रेन मैनेजर) शामिल हैं।इन रेलकर्मियों ने विगत दिनों ड्यूटी के दौरान असामान्य परिस्थितियों एवं संभावित खतरों की समय रहते पहचान कर सराहनीय कार्य किए। इनमें जेसीबी के अचानक ट्रैक पर आने पर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को दुर्घटना से बचाना, ब्रेक वैन से धुआं एवं हॉट एक्सल की पहचान, रेल फ्रैक्चर देखना।

शिक्षा विभाग बना वसूलीबाजों का चारागाहः कांग्रेस

रायपुर। जनगणना और एसआईआर जैसी अत्यंत संवेदनशील और कानूनी रूप से प्रतिबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच चल रहे बेलगाम तबादला उद्योग पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि इस सरकार में तबादला कोई प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बोली लगाने वाला एक खुला बाजार बन चुका है। चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर जनगणना के समय ट्रांसफर करना, प्रशासनिक अराजकता की पराकाष्ठा है।



सबसे अग्रणी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, छत्तीसगढ़ के शिक्षा के मंदिर को इन लोगों ने वसूलीबाजों का चारागाह बना दिया है, जहां अर्धवार्षिक परीक्षा के समय गरीब बच्चों की पढ़ाई दांव पर लगी है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि आज छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से गर्त में धकेल दिया है। भारत सरकार और चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनगणना और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ड्यूटीरत कर्मचारियों-अधिकारियों का ट्रांसफर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन, साय सरकार में नियमों की बलि चढ़ाकर खुलेआम तबादला उद्योग चलाया जा रहा है।

सुकमा में रिमझिम बारिश का दौर जारी, किसानों की चिंता बढ़ी

सुकमा। जिला मुख्यालय में पहले चक्रवात अर्नब और अब मुरासु के असर से जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बीती रात तेज बारिश के बाद बुधवार सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और दिपावली की रौनक भी फीकी पड़ गई है। सबसे ज्यादा चिंता किसानों को सता रही है, क्योंकि खेतों में धान की फसल पककर तैयार है और कटाई का समय नजदीक है। लगातार बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में खड़ी और कटाई के बाद रखी धान की फसल के खराब होने का खतरा बना हुआ है। किसानों को आशंका है कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही, तो धान की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे समय में बारिश होने से कटाई के काम में भी परेशानी आ सकती है। वहीं दिपावली को लेकर जिला मुख्यालय के बाजार में दुकानदारों ने तैयारियां की हैं। दुकानें सजाई गई हैं और त्योहार से जुड़ी सामग्री भी उपलब्ध है। हालांकि लगातार बारिश के कारण खरीदारी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बुधवार सुबह से हो रही रिमझिम बारिश के चलते बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम दिखाई दे रही है।



नक्सल प्रभावित के 50 ग्रामीण पहली बार ट्रेन से पहुंचे गुजरात



रायपुर। बस्तर के जंगलों से निकलकर गुजरात के एकता नगर तक पहुंची यह यात्रा केवल 50 ग्रामीणों का सफर नहीं थी, बल्कि बदलते सुकमा की एक ऐसी तस्वीर थी, जिसमें पहली बार ट्रेन में बैठने का उत्साह भी था और देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय आयोजनों में से एक का हिस्सा बनने का गौरव भी। कभी नक्सल चुनौती के कारण चर्चा में रहने वाले सुकमा के ग्रामीणों ने गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह और भव्य परेड को अपनी आंखों से देखा। जब परेड में छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने कदमताल की, तो सुकमा से पहुंचे ग्रामीणों ने तालियों की गूंज के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। सुकमा जिले के अलग-अलग गांवों से आए 50 नागरिकों के इस दल के लिए गुजरात की यात्रा कई मायनों में खास रही। इनमें बड़ी संख्या ऐसे ग्रामीणों की थी, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार ट्रेन से सफर किया। गांवों की परिचित सीमाओं से बाहर निकलकर लंबी रेल यात्रा करना, नए प्रदेश को देखना और राष्ट्रीय स्तर के भव्य समारोह में शामिल होना उनके लिए एक नया अनुभव था।

छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनाने पर जोर

छत्तीसगढ़ बनेगा देश का नया फिल्म हब

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक, पर्यटन और रोजगार के खुलेंगे नए द्वार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण (फिल्म शूटिंग) को प्रोत्साहित करने और पर्यटन के बहुमुखी विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख और लोकप्रिय फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है।

मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिनेमैटिक और प्राकृतिक दृश्यों की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य के अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध पर्यटन स्थलों को देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशभर में फिल्म शूटिंग के लिहाज से उपयुक्त और संभावनाशील नए स्थलों की पहचान कर उन्हें तेजी से विकसित और प्रोत्साहित किया जाए।



चर्चा के दौरान राज्य की मौजूदा फिल्म नीति को और अधिक व्यावहारिक व प्रभावी बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही, बहुप्रतीक्षित चित्रोत्पला फिल्म सिटी के प्रस्ताव और उसकी संभावनाओं को मूर्त रूप देने को लेकर भी गहन मंथन हुआ। सरकार का उद्देश्य फिल्म मेकर्स के लिए शूटिंग की प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी और आकर्षक बनाना है, जिससे अधिक से अधिक प्रोडक्शन हाउस छत्तीसगढ़ का रुख करें।

मुख्य सचिव ने इस बात पर विशेष बल दिया कि फिल्म निर्माण गतिविधियों के बढ़ने से न केवल पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों, होटल उद्योग और युवाओं के लिए रोजगार के नए और सुनहरे अवसर सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त, बैठक में निफ्टेम (ह्ड्ड्स्रञ्जश्वरू) के प्रस्तावित भ्रमण तथा खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) के क्षेत्र में तकनीकी सुविधाओं एवं प्रशिक्षण के विस्तार को लेकर भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।

इस उच्चस्तरीय बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की प्रबंध संचालक श्रीमती संजीता गुप्ता तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की उप सचिव श्रीमती आकांक्षा शिक्षा खलखो सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एकता नगर में छत्तीसगढ़ का परचम लहराने वाले जांबाज पुलिस अधिकारियों से मिले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा



रायपुर। गुजरात के एकता नगर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में अपने अदम्य साहस, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले पुलिस अधिकारियों से आज उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने परेड में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके अनुभवों को जाना और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के सुरक्षा बलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और सभी के साथ भोजन किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित भव्य परेड में छत्तीसगढ़ के जवानों की सहभागिता पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण था। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। जब हमारे जवान पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और गर्व के साथ कदम से कदम मिलाकर मार्च कर रहे थे, तब वह दृश्य अत्यंत भावुक और गर्व से भर देने वाला था। हमारे जवान केवल एक परेड में हिस्सा नहीं ले रहे थे, बल्कि वे पूरे देश के सामने छत्तीसगढ़ के साहस, संघर्ष और बदलते बस्तर की नई पहचान प्रस्तुत कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विशेष रूप से बस्तर फाइटर्स की महिला कमांडो के शानदार प्रदर्शन की सराहना की।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.